असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 दिसम्बर, 2016

टर्न-1/आजाद

षोडश विधान-सभा
चतुर्थ सत्र

वृहस्पतिवार,तिथि 01 दिसम्बर,2016 ई0
10 अग्रहायण,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अभी हमलोग आपसे मिल करके, एन0डी0ए0 के सभी माननीय सदस्यों ने मिल करके आपसे आग्रह किया था कि जो घटना घटी 29 तारीख को विधान सभा के अन्दर में और जो स्थिति उत्पन्न हुआ था, हमने दो बातों को रखा था महोदय कि जिस तरह से सत्ताधारी दल के लोगों ने वेल में आकर के जो परिस्थिति उत्पन्न किया, टेबुल पर चढ़ गये लोग और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने का काम किया और माननीय विधायिका श्रीमती गायत्री देवी के साथ जो आचरण किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, इसके लिए हमलोगों ने आपसे मिलकर अभी आग्रह किया, हमलोगों का दो विषय है, एक विषय यह है कि उन सदस्यों को रामदेव राय जी को, फातमी जी को, अमीत जी को जिन्होंने अमर्यादित आचरण किया, उनके निलंबन का मांग किया था और दूसरी मांग थी कि पहली बार विधान सभा में सत्ताधारी दल के द्वारा वेल में आकर के जो परिस्थिति उत्पन्न किया गया महोदय, इसके लिए निवेदन किया था निन्दन प्रस्ताव का तो पुनः महोदय, आपसे, आसन से आग्रह है, आपसे न्याय की उम्मीद है, आप ऐसा करें ताकि हम सदन को चलाने में पूरा आपको सहयोग देने का काम करें ।

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, यह बात सही है कि आपने इन बातों को

(व्यवधान)

जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे और अब हम बोल रहे हैं तो संजय सरावगी जी आपको डिस्टर्ब कर मेरी बात भी नहीं सुनने दे रहे हैं ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, ये कह रहे हैं कि गौर से सुनिये अध्यक्ष महोदय की बात ।

अध्यक्ष : इसका मतलब कि ये कहीं दूसरी तरफ देख रहे थे, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इनको कन्डेम कर रहे हैं ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उस दिन भी उठाया था और आज भी उठाया है । आपके इस महत्वपूर्ण विषय का निष्पादन जो संसदीय प्रणाली

का चरम बिन्दु होता है, जो सबसे गंभीरतम तरीके से उसका निष्पादन हो सकता है, उस रूप में किया गया है । जिन सदस्यों का, जिन आचरणों का या फिर सत्तापक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से जिन-जिन सदस्यों का अशोभनीय या असंसदीय आचरण हुआ है, उन सभी की निन्दा की गई है । जो गलत बातें कही गई हैं उसकी निन्दा की गई है, सभी दल के नेताओं ने उठकर उसकी निन्दा की है और खेद प्रकट किया है । अब इससे आगे और कैसे इसका निष्पादन हो सकता है ? अगर कोई माननीय सदस्य टेबुल पर चढ़ गये थे, उसकी निन्दा की गई है । आज से पहले भी चढ़े थे, इस सत्र से पहले भी चढ़े थे । उसके संबंध में भी आसन से नियमन दिया गया था और मैंने बार-बार कहा है कि सत्तापक्ष या विपक्ष की जिम्मेवारी अलग-अलग हो सकती है लेकिन जहां तक सदन के अन्दर व्यवस्था या नियम के पालन की बात है तो वह हर सदस्य का व्यक्तिगत आचरण माना जाता है । इसलिए नियम लागू करने के बारे में, सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष के अलग-अलग सदस्यों के लिए, अलग-अलग आचरण के लिए, अलग-अलग नियम, प्रावधान तो है नहीं । अगर कोई माननीय सदस्य नियम तोड़ते हैं, असंसदीय आचरण करते हैं तो उसके निष्पादन का जो तरीका है, वह सभी के लिए एक है । ऐसा तो है नहीं कि कोई राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उनके लिए यह है और दूसरे दल के लिए यह है, निर्दलीय के लिए यह है । इसलिए मैंने आपको बराबर कहा है कि इस आसन की निष्पक्षता, इस आसन का न्यायपूर्ण जो नियमन होता है, कृपया उसको सभी सदस्यों के लिए समान रहने दीजिए अन्यथा आज अगर इस आसन से पलड़ा इधर-उधर झुकने लगेगा तो यह संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं होगा और आपने जिन बातों की चिन्ता प्रकट की है, सारा सदन आपकी राय से इत्तफाक रखता है । सारे सदन ने आपकी राय उचित मानी है और सारे सदन ने उस आचरण, उन बातों की निन्दा की है। इसलिए अब आपसे आग्रह है कि कृपया सदन की कार्यवाही में सहयोग करिए, आप के ही कतिपय माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न है । अगर आप सरकार से जनहित में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सवाल के माध्यम से उत्तर जानना चाहते हैं तो अभी ढेर सारे सवाल इसमें ऐसे हैं, जिससे कि बिहार की जनता की समस्याओं के समाधान का रास्ता प्रशस्त हो सकता है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि सदन की कार्यवाही चलने दें । आपने जो भी कहा है, हम ही नहीं, आसन ही नहीं, सारा सदन आपकी बातों से सहमत है कि इस तरह के अशोभनीय आचरण, अशोभनीय व्यवहार, अशोभनीय बातें सदन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सदन बिहार की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है । यदि हम और आप मर्यादित आचरण नहीं करेंगे तो इससे बिहार की जनता अपमानित होती है । इसलिए आपसे आग्रह होगा कि सदन की कार्यवाही में सहयोग करें और आप ही के सदस्य का तारांकित प्रश्न 350वें नम्बर पर है ।

श्री संजय सरावगी जी को प्रश्न पूछने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, आपके विचारों का मैं आदर करता हूँ । हमलोगों की चिन्ता महोदय, इस बात की है कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो विधान सभा में, इसीलिए हमलोगों ने कहा था कि कम से कम आप इसपर कड़ा एक्शन लेते, निलंबित कर दिये होते तो स्थिति बहुत पहले समाप्त हो जाती। पुनः महोदय, आपसे आग्रह है कि आपने जिन बातों को कहा है, उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं । आपने सही कहा है, हम सहमत है कि सदन चले लेकिन चिन्ता इस बात की है कि यदि आपके स्तर से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा हमलोगों का चिन्ता का विषय है, इसलिए महोदय, मैंने आग्रह किया है कि .....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, आप सही कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति, आप संजय जी से क्या सलाह करते हैं, हम बार-बार कहते हैं कि वे आपको सही दिशा में नहीं ले जायेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं न ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, ये कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि आपकी बात सुनेंगे, इनको भरोसा है कि आप इनकी बात आज मान लेंगे, इसलिए ये बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष : वह भरोसा नहीं है, वह विश्वास है और वह उदाहरण पर आधारित है कि इन्हीं की बात पर हम ही नहीं, आसन ही नहीं, सारे सदन ने इनकी राय से इत्तफाक जाहिर किया है । हम बराबर कहते हैं कि सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में फर्क यह आसन कैसे कर सकता है ? आपके ही सामने लिखा हुआ है कि - ''संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंगे माने जाते हैं ।'' इधर भी लिखा हुआ है, आप इधर पढ़कर क्या रेफर करना चाहते हैं, बताईए । हम पढ़ रहे हैं और हम रोज यही पढ़ते हैं । इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका मतलब है कि सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष । जहां तक सदन के अनुशासन की बात है, इसमें फर्क नहीं किया जा सकता है । जो भी अनुशासन के नियम, प्रावधान हैं, वह सभी दल के और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों पर बराबर रूप से लागू होते हैं, इसीलिए माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : सर, हमलोगों ने परसों कोई ऐसा आचरण नहीं किया था .....

अध्यक्ष : हम तो अभी की बात कह रहे हैं न ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, हमलोगों ने कोई ऐसा आचरण नहीं किया परसों .....

अध्यक्ष : आपको अभी तक किसी ने कुछ कहा है क्या ?

श्री संजय सरावगी : ऐसा कोई आचरण नहीं हुआ है सर परसों ।

अध्यक्ष : गिनाने लगेंगे तो बहुत चला जायेगा संजय जी ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : महोदय, हमलोग रिजल्ट नहीं देख रहे हैं । आपसे उम्मीद है, आपसे हमलोगों की अपेक्षा है कि आप न्याय देंगे । यदि आप न्याय नहीं देंगे तो लोकतंत्र में हम अपनी आवाज को रखेंगे महोदय । हमारा जो स्टैंड एन0डी0ए0 का है....

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : माननीय मॉझी जी भी साथ में गये थे महोदय और उन्होंने मिलकर सारी बातों को रखने का काम किया है ।

अध्यक्ष : देखिये नेता प्रतिपक्ष, कल वहां सर्वदलीय बैठक से लेकर यहां तक आप सब लोगों ने, कल आपने उसको माना भी था कि सदन में प्ले कार्ड और तख्तियां नहीं आयेगी, अभी से संजय सरावगी हाथ में लेकर के तख्तियां लहरा रहे हैं जबकि उसको सदन में लाना नहीं है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : मॉझी जी भी हमलोगों के साथ गये थे और उन्होंने भी आग्रह किया था कि .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, आप सवाल पूछिए ।

प्रश्नोत्तरकाल

<u>तारांकित प्रश्न</u>

<u>तारांकित प्रश्न सं0-350(श्री संजय सरावगी)</u>

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : सवाल नहीं पूछियेगा ? माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह ।

टर्न-2/अंजनी/01.12.2016

(इस अवसर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर एक साथ कुछ बोलने लगे-व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-351(श्री विरेन्द्र कुमार सिंह)</u>

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी तक किसकी सुन रहे थे ? अभी तक आपकी ही सुन रहे थे ।

श्री(डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अतिक्रमित नदी को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे दो माह में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए, दो माह में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, नवीनगर के पुनपुन नदी में जो अतिक्रमण है, उसमें माफियाओं का घर बना हुआ है और वे बहुत ही प्रभाव रखते हैं । ध्यानाकर्षण आने के बावजूद, मापी हो जाने के बावजूद उसपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक उसको डिमॉलिश करने की कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : कबतक ?

(व्यवधान)

श्री (डॉ0) मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अतिक्रमण हटाने की प्रकिया जारी है और उसे दो माह के अन्दर में उस स्थान से हटा दिया जायेगा।

अध्यक्ष : दो माह में ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-352(श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह)</u>

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-4351 दिनांक 06.07.2016 एवं अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-7524 दिनांक 18.10.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, पं0 चम्पारण से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007.....

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है, वह सुनायी नहीं दे रहा है ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-4351 दिनांक 06.07.2016 एवं अर्द्धसरकारी पत्र संख्या-7524 दिनांक 18.10.2016 द्वारा जिला पदाधिकारी, पं0 चम्पारण से बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3 में उल्लिखित शर्त्तों की पूर्त्ति करने वाले ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने हेतु विहित प्रपत्र में आवश्यक सूचना अभिलेख साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध हाने पर नियमतः कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट । संजय जी, आप जितनी अच्छी बात करते हैं, उतना ही उल्टा आचरण करते हैं । आप पहले मेरी बात सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

आप अभी कह रहे हैं कि सदन तो और्डर में है नहीं और प्रश्न-काल चलाते हैं । सदन किनके कारण डिजऑर्डर में है ? यह अव्यवस्था किसके कारण है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, आपसे आग्रह है, हम चाहते हैं कि सदन चले । महोदय, लेकिन जो स्थिति का निर्माण हुआ है, उसमें संजय जी नहीं, सत्ताधारी दल के लोग जिम्मेवार हैं । यदि आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो बहिष्कार करेंगे ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आप बताइए कि अभी 15 मिनट की कार्यवाही चली है, इस 15 मिनट की कार्यवाही में 08 मिनट आप बोले हैं और अब आप कह रहे हैं कि यदि हमारी बात नहीं सुनियेगा ! तो हम सुन किसकी रहे थे ?

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो । कार्रवाई की अपेक्षा है और कार्रवाई हो । आप कार्रवाई करें, उन सदस्यों को निलंबित करने की कार्रवाई करने का काम करें । हमें आपसे काफी उम्मीद और आशा है कि आप न्याय करेंगे । इसलिए पुनः आपसे आग्रह, अनुरोध है कि उन सदस्यों को आप निलंबित करें, हाउस को और्डर में लाकर .....

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, नेता विरोधी दल लगातार कुछ कह रहे हैं सदन में और सदन जब और्डर में रहे तब न नेता विरोधी दल की बात सुनी जायेगी । आसन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी । हाउस तो और्डर में है नहीं, पहले तो अपने माननीय सदस्यों को नेता विरोधी दल अपने स्थान पर जाने का आग्रह करें, तब वे अपनी बात कहें तो अच्छी बात होगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो हालात पैदा हुए हुए हैं, उसके लिए सत्ता पक्ष के सदस्य जिम्मेवार हैं.....

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री इतना ही कह रहे हैं कि आपको जो कहना है इन लोगों को बैठा दीजिए और बोलिए । इतना ही तो कह रहे हैं ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, जो हाउस में बात चल रही है और हमारे सत्ताधारी दल के माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हाउस डिजऑर्डर है तो इसके लिए जिम्मेवार विपक्ष के लोग नहीं हैं । हमने तो उदाहरण दिया है कि 28 तारीख से कितना बेहतर तरीके से हाउस चला । हमलोगों ने काफी सहयोग किया लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं..

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष उन्हीं बातों को रख रहे हैं, जिन बातों की चर्चा कल दो बार उन्होंने किया और आज भी दो बार किया । एक ही बात की चर्चा बराबर कर रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, मुझे पहले अपनी बात को पूरी करने दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो हालात और परिस्थिति का निर्माण हुआ है और हमारी मजबूरी है कि जो हालात पैदा हुए हैं और जो माननीय विधायिका के साथ घटना घटी है और जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं ? एक महिला विधायिका को धमकी देना क्या उचित है, क्या न्यायोचित है ? महोदय, विपक्ष के लोग वेल में इसलिए गये हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है । महोदय, हम आपसे फिर आग्रह कर रहे हैं कि आज जो हालत विधान सभा में पैदा हुआ है, यदि उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो आर0जे0डी0 के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, इसके लिए हमलोग जिम्मेवार नहीं हैं, विपक्ष के लोग जिम्मेवार नहीं हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्री जी आपको कुछ कहना है ? सरकार की सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

सरकार की सुनिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो गतिरोध हुआ, सदन में गतिरोध के बाद आसन की तरफ से पहल हुई, सभी दलीय नेताओं की आपने बैठक बुलायी और सभी लोग सहमत हो चुके थे, उसके बाद माननीय विपक्ष के नेता उठकर चले गये । महोदय, आप भी रास्ता निकालना चाहते हैं और सरकार भी रास्ता निकालना चाहती है । सदन को चलाने की जवाबदेही सिर्फ सत्ता पक्ष पर नहीं है, सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है । अमर्यादित ढंग से अगर विपक्ष के लोग कोई व्यवहार करते हैं तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए लेकिन वे प्रायश्चित करने में नहीं उसको लीगलाइज करने में लगे हुए हैं । तो लीगलाइज करने से समस्या का हल नहीं होता है और जिस प्रकार से पिछले सदनों में, आपने ठीक ही कहा कि कार्रवाई का जो मापदंड है, कार्रवाई का जो पैमाना है, वह पिछले सदन में जो माननीय सदस्य द्वारा आचरण और व्यवहार हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष के द्वारा किया गया हो, समान रूप से किया जायेगा, तो इसपर माननीय विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अगर कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से उन्होंने कार्यवाही में हिस्सा लिया है तो इसमें डरने की बात क्या है ? तो निश्चित रूप से सदन में इनका मकसद सिर्फ यह है कि इनकी बातों को माना जाय और इनको जो मर्जी आये, मनमुताबिक अपने सदन में इनका व्यवहार रहेगा, इनका आचरण रहेगा, उसपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं होगी महोदय।

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : क्रमश:.....इस तरह से सदन नहीं चलता है । सरकार के पक्ष में भी जो लोग बैठे हैं, वे भी अपनी मर्यादा को बरकरार रखना चाहते हैं । उनकी मर्यादा को आप तार-तार कीजिएगा तो निश्चित रूप से लोगों में गुस्सा पैदा होगा, निश्चित रूप से वे प्रतिकार करेंगे और जब वे प्रतिकार करते हैं तो आपको बुरा लगता है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए । आप उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं, जब आपकी भावना को ठेस पहुंचती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर दूसरे की भावना को ठेस पहुंचती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है । इस तरह से सदन नहीं चलता है, सदन को चलाने के लिए आप हम सब लोग जिम्मेदार हैं और माननीय स्पीकर महोदय का जो निदेश है, उसका हम सबलोगों को पालन करना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महिलायें दो हैं, जिनके साथ अभद्र व्यवहार होने का आरोप है । इसलिए सुन तो लीजिए और हमने नेता, प्रतिपक्ष से कहा है, यह भी सुन लीजिए

(व्यवधान)

आप प्रेमा जी बैठिए न

(व्यवधान)

हमने नेता, प्रतिपक्ष से कहा है कि अगर आप उचित समझते हैं तो हमारे कक्ष में नेता, प्रतिपक्ष भी रहें, सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे । जिन महिला विधायकों का आरोप है, जिन पर आरोप है, उनलोगों को बुलाकर हम इनके समक्ष सुनेंगे और जो उचित होगा करेंगे, यह भी हमने कहा है। अब क्या चाहिए ?

(व्यवधान)

मेरी समझ से प्रेम बाबू, आपकी बातों का नियमानुकूल और संसदीय प्रणाली के मुताबिक जो भी संभव था, आसन ने उसके निराकरण का उपाय किया है । अब आपसे अनुरोध है कि कृपया सदन संचालन में सहयोग कीजिए ।

(व्यवधान)

सदन में सुनना उचित नहीं होगा न । फिर हमको इनका भी सुनना पड़ेगा और दोनों का सुनना होगा । उसको तय कर लीजिए प्रश्नकाल के बाद।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भाजपा की मा0 सदस्या श्रीमती गायत्री देवी वेल में आकर कुछ बोलने लगी)

विजय जी, यह निर्णय आप नहीं दीजिएगा । अनुशासनहीनता सबके लिए अनुशासनहीनता है । अनुशासनहीनता में सत्तापक्ष और विपक्ष में फर्क नहीं होता है, आप

इतनी बात तो समझिए । आप बैठिए । आपको दूसरे के लिए जो अनुशासनहीन लगता है वह आपके लिए उचित नहीं हो जायेगा । सीधी बात है। सदानन्द बाबू बोलिये।

(व्यवधान)

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, भाजपा के लोग जिस हठधर्मिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और आपने नियमन दो-तीन बार दे दिया है और उसके बाद आपके नियमन का पालन नहीं होता है तो सदन सिर्फ विपक्ष की नहीं है, पूरे सदन में हमलोग भी हैं और इस तरह से नहीं चल सकता है, विधान सभा को नहीं चलाया जा सकता है । इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय ।

(इस अवसर पर भाजपा के मा0 सदस्यगण वेल में आकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसके पहले भी लोग टेबुल पर चढ़े हैं, उनके साथ क्या हुआ था ? अपने समय में भूलिए मत । (व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–4/अशोक/01.12.2016

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ।

श्री प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष : महोदय, आपने जो अभी आदेश दिया, आग्रह किया हमलोगों से सत्ताधारी माननीय मंत्री, (व्यवधान)अपने गलतियों को छिपाने के लिए और विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे थे महोदय, विपक्ष के लोग .....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : मैं, बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–4(ii) परन्तुक के अधीन षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के अनागत तारांकित प्रश्नोत्तरों (कुल 434) की मुद्रित प्रतियाँ सदन पटल पर रखता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता, विरोधी दल यह तो उस दिन हुआ, आज अभी क्या हो, अभी कार्यवाही....

(इस अवसर पर श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल भी अपने स्थान से लगातार कुछ बोल रहे थे, जो अस्पष्ट था ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

(इस अवसर भा.ज.पा. के माननीय सदस्यगण सभा के वेल में चले आये और नारे लगाने लगे ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : न्याय ही मिलेगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–62(4) के तहत् " बिहार भवन एवं अन्य सनिर्न्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 " की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1) श्री राणा रणधीर, स.वि.स.
2) श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स.वि.स.
3) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स.वि.स.
4) श्री विजय कुमार खेमका, स.वि.स.

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदान की माँग (ग्रामीण विकास विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-176(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण उपर्युक्त सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सत्ता पक्ष की अधिकांश महिला माननीय सदस्याएं सभा के वेल में चली आईं और नारे लगाने लगीं ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्य-काल लिये जायेंगे ।

<u>शून्य-काल</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मो0 नेमातुल्लाह ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत माँझा प्रखण्ड के मुख्य नहर आर0ई0ओ0 पीच से निकलकर देवापुर अकिल टोला होते हुए मंझौलीया आर0ई0ओ0 पीच तक जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, का मरम्मति एवं जीर्णोधार की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा ।

श्री विरेन्द्र कुमार सिन्हा : महोदय, दाउद नगर स्थिति अनुमण्डल अस्पताल में सृजित पद के अनुसार चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं हुआ है एवं अस्पताल में अभी तक उपकरण भी नहीं लगाया गया है ।

अतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अस्पताल में सृजित पदों के अनुसार चिकित्सकों को पदस्थापित करने एवं उपकरण लगाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिला में प्रतिदिन ट्रक भारवाहन क्षमता से तीन गुणा अधिक बालू लेकर सासाराम-चौसा पथ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जिससे सरकार को राजस्व एवं सड़क की क्षति होती है । रास्ते में थाना द्वारा बालू वाहनों से अवैध उगाही की जाती है ।

सरकार से माँग करता हूँ कि बालू का ओभरलोडिंग बन्द किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनोद प्रसाद यादव ।

(व्यवधान जारी)

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड में ग्राम-चॉपी एवं अफजलपुर के सामने बुढ़ी नदी में पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में लोगों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

जनहित में ग्राम-चौंपी एवं अफजलपुर के सामने बुढ़ी नदी में पुल निर्माण कराने की मॉग सरकार से करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री लालबाबू राम ।

श्री लालबाबू राम : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखण्ड मुख्यालय में बाबा साहेब डा0 भीम राम अम्बेदकर जी का आदमकद प्रतिमा एवं चबुतरा की स्थापना करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार को अनुरोध करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद नवाज आलम ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0-3 बलबतरा में बना ब्रिटिशकालीन बलबतरा पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है, किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है । पुल निर्माण निगम के पास लगभग 16 करोड़ 50 लाख रूपये भोजपुर जिला के लिए है । अतः सरकार से इसे बनाने की मांग करता हूॅ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, 30.04.1993 से सेवा से हटाए गए यक्षमाकर्मियों का बिहार विधान सभा के समक्ष 05.01.2016 से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, इस दौरान दो यक्ष्माकर्मी की मृत्यु भी हो चुकी है । मैं जनहित में इन छंटनीग्रस्त यक्ष्मा कर्मचारियों की पुनः सेवा बहाल करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के आबादपुर थाना के आबादपुर गांव में एक पशु चिकित्सा केन्द्र है । इसकी अपनी जमीन तथा भव्य बिल्डिंग है। पर चिकित्सक के अभाव में केन्द्र का जनहित में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं एक योग्य पशु चिकित्सक की नियुक्ति की मांग करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मदन मोहन तिवारी ।

श्री मदन मोहन तिवारी : महोदय, पं0 चम्पारण के जिला मुख्यालय बेतिया में प्रतिदिन जाम की समस्या से आम जनता परेशान है, जाम में फंसे मरीजों की हालात और अधिक खराब हो जाती है । यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु रूट मैप बनाकर नियमित ट्रैफिक संचालन के लिए सरकार से आग्रह करता हूॅ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती बेबी कुमारी ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, सात निश्चय के तहत डायरेक्ट पंपिंग से जलापूर्त्ति का प्रावधान कर चापाकलों का गाड़ा जाना बंद कर दिया गया है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, जलस्रोत विहीन घरों के गरीबों में त्राहिमाम है । पाईप जलापूर्त्ति चापाकल गाड़ा जाए ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आनन्द शंकर सिंह ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, विमुद्रीकरण के कुछ दिनों पहले भाजपा द्वारा बिहार के कई जिलों जैसे औरंगाबाद, लखीसराय, मधेपुरा इत्यादि में करोड़ों की जमीन खरीदगी की गई, जिसमें कोई हैरानी नहीं कि काले धन का उपयोग हुआ है ।

भाजपा द्वारा जमीन खरीदगी की न्यायिक जॉच करवायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, छौड़ाही प्रा0 स्वा0 केन्द्र(बेगूसराय) विगत् 4 नवम्बर को कुछ उपद्रवियों के द्वारा जलाकर, तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया गया है । जिसका शीघ्र न्यायिक जॉच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हो एवं अस्पताल को छौड़ाही के किसी सरकारी भवन में चलने की शीघ्र व्यवस्था हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अमीत कुमार ।

श्री अमीत कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल में निर्धारित लक्ष्य से कम सिजेरियन प्रसव कराया जा रहा है और नवजात का मृत्यु दर भी अधिक है क्योंकि अस्पताल प्रशासन के सहयोग से दलालों द्वारा मरीज को निजी नर्सिंग होम में सिजेरियन प्रसव के लिए वाध्य किया जाता है ।

टर्न-5:ज्योति

01-12-16

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्र में विगत 10 महीनों से जिला प्रशासन की कारगुजारी के चलते बालू की खरीद-बिक्री बंद है जिससे उक्त कार्य में लगे हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं ।

अतएव जनहित में सरकार उक्त क्षेत्र में अविलम्ब बालू की खरीद-बिक्री प्रारम्भ करावे ।

(माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका एवं माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा शून्य काल की सूचना नहीं पढ़ी गयी ।)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर
सरकार (सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, 15 नवम्बर से बिहार में धान क्रय केन्द्रों को चालू कर किसानों से धान खरीद करनी थी लेकिन क्रय केन्द्रों पर ताले लटक रहे हैं । रब्बी की बुआई के लिए जरुरतमंद किसान कम कीमत पर बिचौलियों के हाथों अपना धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं । धान का समर्थन मूल्य भी उनके लागत (1600/-रु0 प्रति क्विंटल) से कम है ।

अत: किसान हित में धान का समर्थन मूल्य 2500/-रु0 प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर 500/-रु0 का बोनस देने तथा तत्काल क्रय केन्दों को चालू कर बिना कागजी खानापूरी के बटाईदारों सहित सभी किसानों से उनके सम्पूर्ण धान की खरीद के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपका जवाब पढ़ा हुआ माना जाता है, इसकी एक प्रति माननीय सदस्य को भी भेजवा दीजियेगा ।

(माननीय मंत्री का जवाब पढ़ा हुआ माना गया)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, राज्य के कुछ जिलों में धान की फसल का अग्रेत्तर कटनी होने की संभावित सूचना पर उन दस जिलों में 15 नवम्बर से किसानों से धान क्रय के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार पटना के पत्रांक 6556 दिनॉक 15-11-2016 द्वारा निदेशित कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ।

कुल दस जिले यथा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्णियॉ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया में 15 नवम्बर से किसानों से धान खरीदगी संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है । जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार औसत सभी जिलों में नमी की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक का बने रहने के कारण धान का क्रय करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि मानक नमी 17 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिप्राप्ति की गई धान से चावल (सी.एम.आर.) बनाने की मात्रा एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा भारत सरकार के एजेन्सी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । फलस्वरुप नमी की मात्रा सामान्य (17 प्रतिशत) होते ही किसानों की धान की खरीदगी सुनिश्चित की जायेगी ।

धान का समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड एवं दिशा-निर्देश के अनुरुप स्वयं भारत सरकार द्वारा ही की जाती है जिसमें लागत मूल्य एवं अन्य व्यय का निर्धारण भी भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा ही किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदगी हेतु किसी विशेष वर्ष में बोनस देने हेतु असमान्य परिस्थिति यथा आपदा/कृषि लागत व्यय में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी/कृषि उपज का स्थानीय बाजार दर पर अत्यंत बढ़ोत्तरी एवं अन्य परिस्थितिजन्य कारणों के कारण ही इसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुरुप बोनस दिया जाना प्रासंगिक होता है ।

प्रासंगिक वर्ष में धान की अच्छी पैदावार एवं बाजार मूल्य पर इसके सामान्य प्रभाव तथा कृषि लागत में कोई विशेष परिस्थितिजन्य कारण उत्पन्न नहीं होने के कारण बोनस देने का निर्णय प्रासंगिक नहीं है ।

इस वर्ष धान क्रय हेतु राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय द्वारा दूसरे के जमीन पर खेती करने वाले (सामान्य सम्बोधन बटाईदार) छोटे एवं मंझौले किसानों से धान क्रय की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल एवं सुगम बनाते हुए मात्र उनके स्वघोषणा पत्र पर ही धान क्रय करने की नीति सुनिश्चित की गई है ।

धान क्रय व्यवस्था के प्रबंधन हेतु पूर्ण पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु किसानों से दूसरे के जमीन पर खेती करने वाले (सामान्य सम्बोधन बटाईदार) किसानों से उनका मात्र आई0डी0प्रूफ कागज के रुप में ली जाती है अन्य वर्ग के किसान जो अपने जमीन पर खेती करते हैं उनसे उनका भूस्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा हाल के मालगुजारी रसीद किसी एक कागजात सहित उनके आई0डी0प्रूफ पर ही इस वर्ग के किसानों से धान क्रय की नीति सुनिश्चित की गई है ।

इस प्रकार राज्य के सभी वर्ग के किसानों से व्यापक पैमाने पर कृषकों को उनके धान के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है ।

अध्यक्ष : श्री रामसेवक सिंह ।

सर्वश्री रामसेवक सिंह एवं अन्य दो सभा सदस्यों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना
तथा उसपर सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य

श्री रामसेवक सिंह : महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के राज्यादेश संख्या - 6एस0एस0(6)42/2014-8817 दिनाँक 14-09-2016 के द्वारा जीविका के माध्यम से समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अन्तर्गत 2016-17 में कुल 9.96 करोड़ (नौ करोड़ छियानवे लाख) रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिससे 8300 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति परिवारों (अनुसूचित जाति-6500, अनुसूचित जनजाति-1800, कुल -8300 परिवार) के बीच उन्नत नस्ल की तीन बकरियों का नि:शुल्क वितरण किया जाना है । अबतक राशि जीविका को उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र चार माह शेष है । स्वीकृत राशि जीविका को उपलब्ध कराने के पश्चात् राज्य के सभी प्रखण्डों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाना है ।

अतः इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल रुपये 1658.00 लाख (सोलह करोड़ अन्ठावन लाख) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजना अन्तर्गत '' समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना '' के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य में उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी, इच्छुक बकरी पालकों/गरीब परिवारों के बीच जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरण तथा बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्रों में गोट फार्म (20 बकरी-1-1 बकरा की क्षमता) की स्थापना पर अनुदान एवं प्रशिक्षण देकर बकरी/बकरा पालन को प्रोत्साहित किए जाने निमित्त राज्यादेश संख्या -6 एस0एस0(6) 42/2014-2817 दिनॉक 14-09-2016 निर्गत की गयी है । जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पूर्ण राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के तहत उपलब्ध राशि से अनुसूचित जाति के लगभग-6500 परिवारों एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत उपलब्ध राशि से अनुसूचित जनजाति के लगभग-1800 परिवारों अर्थात् कुल 8300 परिवारों के बीच उन्नत नस्ल की तीन प्रजनन योग्य बकरियों का निःशुल्क वितरण की योजना है ।

राज्यादेश की कंडिका - 5 (A)(IX) के आलोक में जीविका से प्राप्त अधियाचना के आधार पर निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा एकमुश्त राशि जीविका को उपलब्ध करायी जानी है ।

सम्प्रति जीविका से दिनॉक 14-11-2016 को पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत जीविका को कुल रु0 80 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गयी थी । जीविका के द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण राशि निकासी में कोषागार द्वारा वित्त विभाग का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की गयी है । फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि जो जीविका को दी जानी है, की निकासी नहीं हो पा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जवाब की प्रति माननीय सदस्य को भेजवा दीजियेगा ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में द्वितीय तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रुझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज विभिन्न वर्षों की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित प्रतिवेदन सं0-598, सहकारिता विभाग से संबंधित प्रतिवेदन सं0-599, खन एवं भूतत्व विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या-600, भवन निर्माण विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या-601 और नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित प्रतिवेदन सं0-605 तथा 606 को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-239 के तहत् सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-6/विजय/01.12.16

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरणी में सम्मिलित अनुदानों के मांगों की कुल संख्या-36 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है। किसी एक मांग की अनुदान के प्रस्ताव पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंध) के द्वारा किया जायगा ।

अब मैं मांग संख्या-42 ग्रामीण विकास विभाग को लेता हूं जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	20 मिनट
सी.पी.आई. (एम.एल.)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट
	कुल- 180 मिनट

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूत्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2016 के उपबंध के अतिरिक्त

11,85,05,13,000/-(ग्याहर अरब पचासी करोड़ पांच लाख तेरह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री अरूण कुमार सिन्हा से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा अनुपस्थित हैं ।

चूंकि कोई कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, अतः माननीय मंत्री के अनुदान मांग के मूल प्रस्ताव पर ही विमर्श होगा ।

माननीय सदस्य, श्री चन्द्रसेन प्रसाद ।

श्री चन्द्रसेन प्रसादः अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका मिला है । इसके लिए हम अपनी ओर और महागठबंधन की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में जो भी कुछ हो रहा है, पूरे देश के लिए आज उसको देखने और समझने की जरूरत है । महागठबंधन की सरकार जब दोबारे सत्ता में आयी तो सत्ता में आने के पहले जनता के मांगों पर बिहार का विकास कैसे हो, बिहार पूरे देश में एक नंबर पर कैसे आये, इस पर जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी । सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की भावना को देखते हुए जो उन्होंने बिहार के विकास के लिए न्याय के साथ विकास के लिए, बिहार की खुशहाली के लिए जो उन्होंने नीति तय की उस नीति के आधार पर सबका विकास बिहार में हो इसके लिए उन्होंने सात निश्चय बिहार में लागू करने का काम किया । इसके लिए हम अपने विधान सभा की ओर से और पूरे महागठबंधन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आज हमें देखने को मिलता है पूरे देश में क्या हो रहा है और बिहार में क्या हो रहा है यह देखने को नजदीक से मिलता है । ग्रामीण विकास के सवाल पर आज डिबेट पर कुछ बोलने का मौका मिला है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सात निश्चय में ग्रामीण विकास विभाग की अग्रणी भूमिका है । इसलिए बिहार में ग्रामीण विकास विभाग जो सात निश्चय का अंग है, चाहे शौचालय का सवाल हो, चाहे जीविका का सवाल हो, चाहे मनरेगा का सवाल हो, चाहे आवास योजना का सवाल हो । सबसे पहले मैं आवास की ओर जाना चाहता हूं । महोदय, पहले इंदिरा आवास पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में चलाया जा रहा था ।

क्रमशः

टर्न–7/01.12.2016/बिपिन

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार आर्थिक जनगणना, जातीय जनगणना हुआ । उस जनगणना के आधार पर इस बार पूरे बिहार में जनगणना का असर देखने का मौका मिला । महोदय, आवास के सवाल पर हम कहना चाहते हैं, विपक्ष नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि इन्दिरा आवास में पहले 75 और 25 परसेंट का आंकड़ा था । उसको घटाकर 60–40 का आंकड़ा दिया गया । बिहार की हिस्सेदारी 40 परसेंट उसमें है, 60 परसेंट जो है भारत सरकार का है । महोदय, आपके माध्यम से और महागठबंधन सरकार के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब 60–40 का आंकड़ा है तो इन्दिरा आवास के जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो लागू किया गया । मैं कहना चाहता हूं, सदन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसको लागू करने का काम करें । यही हमें सदन से उम्मीद है, अध्यक्ष महोदय।

महोदय, बिहार में जो आवास योजना चलाया जा रहा है, केन्द्र की सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया, वह काफी त्रूटिपूर्ण रहा । बिहार सरकार उसी पर चल करके, लेकिन बिहार सरकार ग्रामीण विकास, खास करके आवास योजना को हिन्दुस्तान में अगर आवास योजना पर हुआ, गरीबों को आवास देने का काम हुआ तो हिन्दुस्तान में भारत में बिहार का दो नम्बर पर अभी अपना रेकर्ड बनाने का काम किया है । यू.पी. और उसके बाद बिहार । महोदय, हम बताना चाहते हैं सदन के माध्यम से विरोधी दल के लोगों को कि आज यह जो मोदी की सरकार है, आवास योजना, एक नम्बर पर यू.पी., दूसरे नम्बर पर बिहार है, तो हम कहना चाहते हैं महोदय कि बिहार आज भी जो है आवास योजना के क्षेत्र में, खासकर महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लालू यादव के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसका कोई उदाहरण नहीं है महोदय । बिहार में काम हो रहा है । महोदय, स्वच्छता के सवाल पर हम कहना चाहते हैं, स्वच्छता के सवाल पर मोदी जी एजेंडा बनाए थे, स्वच्छता के सवाल पर फोटो खींचवाने का काम किया लेकिन महोदय, बिहार में स्वच्छता के सवाल पर, शौचालय के सवाल पर जो बिहार ने पूरे देश में दर्पण दिखाने का काम किया है, सात निश्चय में वह भी एक अंग है महोदय । महागठबंधन का जो सात निश्चय है उसमें एक अंग है महोदय । अध्यक्ष महोदय, शौचालय के सवाल पर जो सात निश्चय में कहा गया है, ग्रामीण विकास विभाग पूरे बिहार में हर घर को शौचालय देने का काम करेगी । महोदय, 12 हजार रूपया प्रत्येक वैसे परिवार को जिनके पास शौचालय नहीं है, उनको 12 हजार रूपया देने का काम करेगी । शौचालय में भी भारत की सरकार, मोदी की सरकार ने वहां पर भी सौतेलापन व्यवहार किया है, मात्र चार हजार रूपया । आठ

हजार रूपया बिहार सरकार देती है और चार हजार रूपया भारत की सरकार देती है । महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, शौचालय के क्षेत्र में एक तरफ तो पूरे देश में डंका पीटने का काम कर रहे हैं कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में भारत को एक नम्बर पर लाना चाहते हैं लेकिन महोदय, यहां ढकोसला है । बिहार सरकार हर घर में शौचालय देने का निश्चय किया है । महागठबंधन की सरकार हर घर को शौचालय देने का काम किया है । आठ हजार लगभग ऐसे परिवार हैं, चाहे शहर में हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हों, उनके पास शौचालय नहीं है । जमीन है लेकिन शौचालय नहीं है । कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको न जमीन है, न शौचालय है । इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पूरे बिहार में वैसे लोगों को सामूहिक शौचालय देने का काम किया है महोदय । यह एक भारत के इतिहास में, भारत के ग्रामीण विकास विभाग में एक अपना दर्पण देने का काम किया है महोदय । इसलिए हम ग्रामीण विकास के मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं । आदरणीय नेता नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं । महोदय, जब पूरे बिहार में घर-घर में शौचालय 2020 तक बन जाएगा तो बचा क्या ?

महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, जीविका के क्षेत्र में भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जीविका के क्षेत्र में भी बिहार पूरे देश में एक मोडल देने का काम किया है । खासकर हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि जीविका एक ऐसा संगठन बनकर उभरा है जिसके माध्यम से खासकर महिलाओं को जो 50 प्रतिशत आबादी हमारे बिहार में रहती है, उस आबादी को उस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में और जागरूकता के क्षेत्र में जीविका के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है । जीविका के माध्यम से खासकर महिलाओं के विकास को देखने को मिलता है । महोदय, मेला में जीविका द्वारा जो आज बाजार में सामान ला रही है, महिलाएं अपने हुनर से, अपने मेहनत से काम करती हैं और एक-से-एक लोगों के काम आने वाला सामान बनाकर बाजार में जब उनका सामान आता है तो पर्यटक जब बिहार में आते हैं तो जीविका के सामान को बड़ा ही गौर से देखते हैं और आदरणीय नेता नीतीश कुमार, आदरणीय नेता लालू यादव और सोनिया गांधी का तारीफ करते हैं कि आखिरकार कौन-सा ऐसा खूबी जीविका में है कि अपने हुनर से इसको बनाने का काम करती हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

और सस्ता, सबसे खास बात यह है महोदय कि खांटी और कम मूल्य में बनकर आ जाता है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी को महागठबंधन को जीविका के लिए मैं उनको अपनी ओर से और सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि महिलाएं जीविका के माध्यम

से, जीविका के बदौलत, जीविका के महिलाओं ने ही प्रेरणा देकर महागठबंधन की सरकार को पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रेरित करने का काम किया है महोदय, इसके लिए हम पूरे बिहार के जीविका की महिलाओं को और महिलाओं को हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रेरणा से महागठबंधन की सरकार और हमलोगों के माननीय नेता उसको दाबने का काम किया और पूर्ण शराबबंदी का बिहार में एक ऐतिहासिक कदम उठाकर पूरे भारत में एक उदाहरण देने का काम किया है और आज पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और एक हलचल है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया । लेकिन सपने में भी नहीं सोचते थे महोदय । इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि जीविका के माध्यम से और महिलाओं के संगठन के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो पहल किया गया है माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने जिलों का दौरा कर-कर के उन्होंने जो पहल किया है, संगठन को मजबूत किया है । जीविका को चुस्त-दुरूस्त किया है । इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं । इसी तरह बिहार जीविका के माध्यम से आगे बढ़ते रहे ।

महोदय, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में और जीविका के क्षेत्र में आज सात निश्चय में, चाहे नली-गली का सवाल हो, बिजली का सवाल हो...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है। आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, जीविका के महिलाओं को उसमें भी प्रायरिटी दे कर बढ़ाने का काम किया गया है । एक-से-एक काम जीविका के अंदर है ।

क्रमशः

टर्न-8 कृष्ण 1.12.2016

श्री चन्द्रसेन प्रसाद - क्रमश : महोदय, अंत में मैं समय को ध्यान में रखते हुये मनरेगा के सवाल पर कहना चाहता हूं कि मनरेगा के तहत बिहार में जो काम हो रहा है, केन्द्र सरकार ने राशि की कटौती करने का काम किया है । केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास मे जो बाधा डालने का काम किया है, महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐ मोदी की सरकार, जो मनरेगा का पैसा है, उसे बिहार सरकार को रीलीज करने का काम कीजिये ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग भारत के इतिहास में एक दिन अपना परचम फहराने का काम करेगा और माननीय मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार जी 2019-20 में प्रधान मंत्री के रूप में भारत में झंडा फहराने का काम करेंगे । जय बिहार, जय महागठबंधन ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री मो0 नेमातुल्लाह साहब ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के विनियोग विधेयक के अनुदान मांगों के समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

महोदय, ग्रामीण विकास एक रीढ़ है सारे विकास का और खास तौर से जो हमारे कार्यक्रम दिल्ली के सहयोग से चल रहे हैं-मनरेगा, इन्दिरा आवास, जिसमें हमारा भी शेयर होता है, यह रीढ़ है । इन्दिरा आवास के द्वारा बेघर लोगों को घर मिलता है, उनके लिये यह एक बहुत बड़ी आशा की किरण होती है । लेकिन इधर भारत सरकार द्वारा जिस तरह से ग्रामीण विकास में लगातार कटौती करती जा रही है, उससे गरीबों को छत देने में बहुत बाधा पहुंच रही है । महोदय, जिस तरह से हमलोग गरीबों को आशा दिला कर आये थे कि हर व्यक्ति को छत मिलेगा, हर व्यक्ति को घर मिलेगा, लेकिन जिस तरह से सरकार की ओर से कटौती की जा रही है इन्दिरा आवास में तो उसके कारण अभी देना संभव नहीं हो रहा है ।

महोदय, दूसरी बात मनरेगा है । मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, देहात में रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को, गरीबों को लेकिन उसमें भी बहुत सारी परेशानियां हो रही है । हर डी0एम0,डी0डी0सी0 को एक सरकुलर भेजा गया कि मनरेगा के तहत रोड भी बने, पुल-पुलिया भी बने और जो छोटी-छोटी योजनायें हैं, उनको भी लिया जाय । लेकिन इस तरह का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है । महोदय, इस पर भी विचार करना होगा । महोदय, जो ग्रामीण विकास का काम है, नीचे तबके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचना, कमजोर लोगों को उठाना, यह मंशा है, सात निश्चय में तय किया गया है, जो महागठबंधन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सी0एम0 जी का यह सपना था कि जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको हम वादा करके चुनाव जीत कर आये हैं, वह सात निश्चय, चाहे हमारा महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आर0जे0डी0 हो, चाहे ज0द0यू हो, सब लोग एक साथ मिल कर तय किये थे कि 7 निश्चय में जो वादा किये थे, उसको पूरा करेगे और जो निचले तबके के लोग हैं, नीचले पायदान पर जो हैं, उनको हम राहत पहुंचायेंगे, इसमें हम सफल हुये हैं । एक साल के अंदर सारे निश्चय को पूरा करने में, सारे वादे को पूरा करने में महागठबंधन की यह सरकार कामयाब हुयी है और उस पर जोर-शोर से काम चल रहा है । चाहे वह शराबबंदी का मामला हो । महोदय, शराबबंदी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, आते के साथ मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सी0एम0 साहब, इनलोगों ने फैसला किया कि शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से होगी और बिहार में शराबबंदी को पूर्ण रूप

से लागू किया गया । स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड के संबंध में वादा किया गया कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिये क्रेडिट कार्ड देंगे, उसको भी 2 अक्टूबर से लागू किया गया। महोदय, हर घर को नल से जल देने की बात जो कही गयी है, उसकी भी शुरूआत हो चुकी है । महोदय, 7 निश्चय में जिस तरह से कामयाबी मिल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आनेवाले वख्त में हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा । वे क्या मुद्दा लेकर आयेंगे ? आज भारत सरकार फंसी हुई है नोटबंदी के चक्कर में । बिना तैयारी किये नोटबंदी कर दिया, पूरे भारत में आज हाहाकार मचा हुआ है, ग्रामीण विकास के तरफ से गरीबों को जो पेंशन जाता है, उन गरीबों को पेंशन नहीं मिल सकता है, पेंशन उनके बैंक के खाते में जाता है, वे भूखे मर रहे हैं, वे अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, हम 500/- रूपया दे कर अपनी गाड़ी में पट्रौल भरवा सकते हैं लेकिन 500/-रू0 लेकर हम किसी होटल में जाकर रोटी नहीं खरीद सकते हैं । पेट्रौल कौन भरवाता है ? बड़े लोगों के पास गाड़ियां है, वह 500/-रू0 के नोट से पेट्रौल भरा लेता है लेकिन गरीब लोग होटल जा कर वहां से भूखे लौट आते हैं । वे रोटी नहीं खरीद सकते हैं । इस तरह से भारत सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है । हम कालाधान के खिलाफ नहीं है । काला धान जल्द-से-जल्द लाये । तुमने वादा किया था कि स्वीस बैंक से कालाधन लायेंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रूपया जमा कर देंगे, उसको उन्होंने नहीं जमा किया और नोटबंदी करके और परेशानी खड़ा कर दिया । इन्होंने पूरे देश के गरीबों को लाईन में खड़ा कर दिया । आज पलायन हो रहा है, गरीब लोग जो बाहर कमाने के लिये गये है, जो गुजरात गये हैं, महाराष्ट्र गये हैं, पंजाब गये है, वे ट्रेन में भर-भर कर अपने घर लौट रहे हैं, अपने-अपने राज्य में लौट रहे हैं, उनका जीना दूभर हो गया है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है । तो महोदय, इस तरह का फैसला किया गया, कभी चाय-चाय कहा गया, कभी लव जेहाद कहा गया । आज क्या हो रहा है, गरीब जब इक्ट्ठा हो रहा है तो हाय-हाय किया जा रहा है, इसलिए भाग गये । माननीय सदस्यों को सदन में आ कर सामना करना चाहिए । डिबेट का सामना नहीं करते हैं, बाधा डालते हैं । अपने-अपने क्षेत्र में सवाल जनता पूछेगी कि तुमको भेजा विधान सभा डिबेट में हिस्सा लेने के लिये, तुमको विधान सभा का बायकॉट करने के लिये नहीं भेजा था । इस का जवाब उनसे जनता मांगेगी । महोदय, आज बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय डिप्टी सी0एम0 तेजस्वी जी के नेतृत्व में, बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार जिस तरह से हर क्षेत्र में अपना काम रहा है, मूलभूत सुविधायें मुह्हैया कराने में जिस तरह से तत्पर हैं, हमको लगता है कि ये लोग असेम्बली को फेस नहीं करना चाहते हैं और न जनता को फेस करना चाहते हैं और न असेम्बली में फेस करना चाहते हैं । महोदय, सात निश्चय में जिस तरह से डी. डी.ओ. की भूमिका रही है, जो शराबबंदी में भूमिका

रही है, वह एक सराहनीय काम रही है । गांव-गांव में जाकर देहातों में जाकर शराबबंदी पर उन्होंने जिस तरह से कंससनेस तैयार किया है, आज क्राईम का ग्राफ बहुत गिरा है । शराब के चलते जो क्राईम बढ़ जाता था, शादी-विवाह में लोग शराब पीकर अंधाधुन जो गोलियां चलाते थे, आज आसानी से शादी-विवाह हो रहा है और किसी तरह की घटना नहीं घट रही है । यह महागठबंधन सरकार की ही देन है । जिस तरह से इनलोगों ने प्रचार किया कि महाजंगल राज है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज असेम्बली में किसने जंगल राज का परिचय दिया है ? असेम्बली में किस तरह से व्यवहार किया है इनलोगों ने । आपकी नजर में कोई छिपी हुई बात नहीं है । आप देखें है स्वच्छ भारत का नारा दिया । स्वच्छ भारत का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था । भारत के संविधान में स्वच्छ भारत की व्यवस्था है । क्रमश :

टर्न-9/राजेश/01.12.16

श्री मो0 नेमातुल्लाह, क्रमशः- पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब मेरी गाड़ी सूर्यास्त के बाद रोड पर जाती है तब मेरे ऑखों से ऑसू टपक जाता है, जब मैं अपनी मां-बहनों को देखता हूँ रोड पर शौच करते हुए, तो मुझे लगता है कि मैं आजाद हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं हूँ । आज आप स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं । आज हमारे आजाद हुए देश में आज भी लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं और लोगों में यह मान्यता है, जबकि अच्छे-अच्छे लोग अपना घर भी बना लेते हैं लेकिन वे शौचालय नहीं बनाते हैं । वे शौचालय क्यों नहीं बनाते हैं ? अगर वे बनाते भी हैं तो वे उसमें शौच करने नहीं जाते है । चूंकि वे लोग भ्रम में हैं । गरीब गॉव-देहात के लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अगर हम अपने घर में शौच करेंगे तो लक्ष्मी नहीं आयेगी । लक्ष्मी वास नहीं करेगी । इसलिए शौचालय बनाने के बावजूद भी वे लोग खेत में ही शौच जाते हैं । इसलिए इसमें लोगों को कन्सेसनेस लाना पड़ेगा । उनमें जागृति पैदा करनी पड़ेगी । जिस तरह से लोगों में शराबबंदी के लिए जागृति पैदा करके शराबबंदी की गयी, उसी प्रकार बाहर खेत में, मैदान में नहीं शौच करें, इसके लिए भी जागृति लोगों में पैदा करनी पड़ेगी । इसलिए जो ग्रामीण विकास विभाग में 12 हजार रुपया शौचालय बनाने के बाद देने का जो निर्णय लिया है, इसमें मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी पहले कहॉ से इसमें पैसा लगायेगा कि वह शौचालय बनाये । उसके द्वारा शौचालय बनाने के बाद आप उनको रुपया दीजियेगा । भाई, कुछ पैसा इनको पहले दीजिये कि ये बनावें, उसके बाद उसको देखिये, उसकी गुणवत्ता को देखिये, उसकी क्वालिटी को देखिये । लेकिन जब गरीब आदमी उसको बना लेगा, उसके बाद उसका भेरिफिकेशन हो जायेगा, तब उसको 12 हजार रुपया मिलेगा । मेरा कहना है कि वह

गरीब आदमी पहले कहॉ से खर्चा करेगा ? हमलोग पंचायतों को स्वच्छ पंचायत बनाना चाहते हैं । हर गॉव को स्वच्छ गॉव बनाना चाहते हैं, तो जो गरीब आदमी है, वह आज भी सोचेगा कि हम 12 हजार रुपया कहॉ से लाये कि हम शौचालय बनाये और 12 हजार रुपये में शौचालय बनता भी नहीं है । आज उसका काफी कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए वह बाहर जाता है शौच करने के लिए, हमारी मॉ-बहनें बाहर जाती हैं शौच करने के लिए । इसलिए हमारा ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि वे इस राशि को बढ़ावें और आप यह भी करें, यह प्रोत्साहन राशि नहीं, आप पहले दीजिये आधा पैसा फिर बाद में पैसा दीजिये, उसके खाता में पैसा दीजिये । इसलिए माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इसमें कुछ निर्णय लें और इसपर कुछ फैसला करें । सभापति महोदय, आज इस देश की हालात बहुत बुरी है । आज हर आदमी परेशान है । जिसके पास पैसा है, वह भी परेशान है और जिसके पास पैसा नहीं है, वह भी परेशान है । हमने सुना कि एक ड्राईवर था । उनके खाते में 25 हजार करोड़ रुपया चला आया । शाम में जब वे गये तो उन्हें मालूम हुआ कि वह पैसा निकल गया । भाई, यह कौन-सा धंधा है ? उसी तरह से मालूम हुआ कि बंगाल में विशेष पार्टी के एक नेता ने एक दिन पहले दो करोड़ रुपया जमा कर दिया । अब वह पैसा कहॉ से आ गया ? आज बिहार में जमीन और पूरे हिन्दुस्तान में जमीन एक विशेष पार्टी के द्वारा कार्यालय के लिए खरीदी जा रही है और इसके लिए पैसा नोटबंदी से दो दिन पहले ही चला गया । पैसा कैश से ट्रान्जेक्शन हो गया तो महोदय आज लोग ऑख नहीं मूंदे हुए हैं । सबकी नजर है । जनता भी देख रही है कि किस तरह से कौन घोटालेबाज हैं और कौन कालाधन कहॉ रखे हुए हैं और कहॉ से लेकर आये है ? इसलिए पहले ये वादा पूरा करें अपना कि जिस तरह से चुनाव में वादा किया था कि हम कालाधन विदेश से ले आयेंगे लेकिन आज देश के गरीबों को लाईन में खड़ा कर दिया बैंकों में लेकिन आज उसमें भी पैसा नहीं है । इन्होंने कॉपरेटिव बैंक में पैसा देना बंद कर दिया, कॉपरेटिव बैंक जनता का बैंक है, गॉव, देहात का बैंक हैं । उसमें आप पैसा नही दे रहे हैं । वहॉ लोग जा रहे हैं । लोगों का उसमें खाता है । उसमें उनका पैसा है, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो इस तरह से न तो वे पैसा जमा कर पा रहे हैं और न ही पैसा अपना निकाल पा रहे हैं तो अब बताइये कि जिनका को-ऑपरेटिव बैंक में खाता है, वह कहॉ जायेगा ? तो इस तरह से परेशानी पर परेशानी बढ़ रही है इस देश में और इस राज्य में । आज आपने एल0पी0जी0 गैस में दाम बढ़ा दिया । आप गरीबों के पेट में रोज-ब-रोज लात मार रहे हैं । आपने 50 रुपया आज गैस में बढ़ा दिया । अब गॉव के गरीब लोग 50 रुपया कहॉ से लायेगें ? 50 रुपया तो बैंक से भी नहीं मिल रहा है । 500 रुपया की कमी आ गयी है, 2000 का नोट ए0टी0एम0 से नहीं निकल रहा है । इस तरह से पाबंदी पर पाबंदी हमलोगों पर लगा

रहे हैं और बिहार के साथ भारत की सरकार सौतेलापन का व्यवहार कर रही हैं । उसी तरह से हमारा जो इंदिरा आवास हैं, आपने उसमें 40 परसेंट राज्य पर भार दिया और आप 60 परसेंट उसमें राशि दे रहे हैं, आपको तो सेंट-परसेंट इंदिरा आवास में राशि देना चाहिए । इंदिरा आवास में पूरा राशि इनको देना चाहिए क्योंकि हमारा बिहार राज्य गरीब राज्य है । हमारे यहॉ गरीब लोग छत के नीचे नहीं रहते हैं बल्कि आसमान के नीचे रहते हैं । इसलिए हमारे यहॉ लोग बेहाल हैं । हमारा इलाका दीयर का है, बॉध के नीचे लोग रहते हैं । वहॉ इंदिरा आवास की घोर कमी है । वहॉ गरीब लोग, दलित लोग, शोषित लोग बसे हुए हैं । जब हमलोग वहॉ जाते हैं तो लोग हमें घेर लेते हैं कि इंदिरा आवास कब आयेगा ? भाई, जब भारत सरकार पैसा देगी तब न इंदिरा आवास बनेगा, तो भारत सरकार इसमें पैसा नहीं दे रही है, वे केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि अभी पैसा आयेगा, तब आपका भी लिस्ट में नाम आ जायेगा । इसलिए परेशानी तो है महोदय । तो इस परेशानी से निबटना पड़ेगा महोदय हमलोगों को, चाहे इसके लिए संघर्ष का तरीका हो, चाहे जो रवैया अपनाये, हमारा जिस तरह से व्यवस्था है, इस व्यवस्था में वे फीट नहीं कर रहे हैं । पहले इन्होंने कहा कि हम विशेष पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देने की बात कहें, तो इस तरह से न तो विशेष पैकेज ही दिया गया और न ही स्पेशल स्टेटस ही दिया गया, तो इस तरह से आज हमलोगों को परेशानी बढ़ रही है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं बिहार को, वे बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और बिहार को पहले पायदान पर रखना चाहते हैं, उनके मंसूबों को ये लोग चकनाचूर करना चाहते हैं, पैसा की कमी दिला करके तो इसको हमलोग चकनाचूर नहीं होने देंगे । चाहे जो भी परेशानियॉ होंगी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमलोग बिहार को आगे बढ़ायेंगे और हम अपने प्रदेश को एक नम्बर पर ले जायेंगे । महोदय, एक बहुत बड़ी बात है । एक समस्या है हमारे कुछ क्षेत्र में, हमारा ग्रामीण रोड जो है..... (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):- माननीय सदस्य आपका समय मात्र दो ही मिनट बचा है ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : जी । महोदय, हमारे क्षेत्र में ग्रामीण सड़के हैं और बहुत सारी सड़के ग्रामीण हैं तो ग्रामीण सड़कों पर पैसा की कमी है । इसलिए आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ग्रामीण सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि गॉव में बसने वाले लोगों को इसका लाभ हो । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय में कहा कि गॉव में जो लोग हैं, वहॉ लोग कच्ची सड़क पर चलते थे और उन्हें पानी लग जाता था तो उन सारे कच्ची सड़कों को हम पी0सी0सी0 करा देंगे, पक्की सड़के, पक्का नाला बनवा देंगे । इस तरह से गॉवों को हम स्मार्ट बनायेंगे । शहरों को स्मार्ट बनाने की जरुरत नहीं है । अगर हमें विकास करना है तो हमारे गॉवों को स्मार्ट

बनाओ । अगर वह स्मार्ट बनेगा तो बिहार एक नम्बर पर पूरे भारत में जायेगा और आप जानते ही है महोदय कि गॉवों में ही आत्मा बसती है । हिन्दुस्तान की आत्मा देहात में बसती है और अगर देहात के लोग जिंदा रहेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा और अगर देहात–गॉव के लोग कमजोर हो जायेंगे तो भारत और बिहार आगे नहीं बढ़ेगा । इन्हीं बातों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव):– माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

टर्न–10/सत्येन्द्र/1–12–16

श्री रामदेव राय: महोदय,टेबुल पर चढ़ने के लिए जो हमें मजबूर किया है उनको इंतजार करना चाहिए, पहाड़ पर चढ़कर भी उसे एक लात में नीचे गिरा दूंगा । महोदय, पहले ही टोक दिये टेबुल की बात, मैं उधर जाना चाहता नहीं हूँ मैं तो बजट के सिवा आगे नहीं जाना चाहता । महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जो निकासी के लिए मांग पेश की गयी है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, पूरा बजट 44 अरब 61 करोड़ 69 लाख, 5 हजार निकासी के लिए मांग किया गया है उसमें 11 अरब 85 करोड़ 5 लाख 18 हजार अनुपूरक राशि सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए है । यह हमारे सुखद और हमारे बिहार के भविष्य का परिचायक है, 1/4 बजट, 1/4 राशि हम केवल ग्रामीण विकास के लिए दे रहे हैं । ये हमारे मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास के मंत्री जी का योगदान है । इस योगदान को किन शब्दों में चर्चा करूं, सब्र तो नहीं है लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ आंकड़े के साथ, कोई तो नहीं हैं लेकिन ऊपर से जो मीडिया वाले है सुनकर उन्हें बतला सकते हैं । महोदय, 2005 और 2006 में जहां हमारा बजट 22500 करोड़ का था वहीं आज हमारा बजट 1 लाख 44 हजार रू0 का है। यानी बिहार के सर्वांगीण विकास का यह एक प्रमाण है और महोदय ये बजट का पैसा हम समय पर खर्च कर रहे हैं और इसी के कारण आप यह देखेंगे कि हमारे यहां सकल घरेलू उत्पाद जो भारत सरकार का मात्र 8 प्रतिशत है वहीं बिहार सरकार का 12 प्रतिशत के लगभग है । ये किस बात का द्योतक है । हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कड़ी मेहनत के साथ और पक्के इरादे के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामीण विकास उसका एक मुख्य अंग है । हमारे मुख्यमंत्री जी जो सात निश्चय तैयार किये है, ये सात निश्चय नहीं, ये सप्तऋषि है । आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सतभईया कहा जाता है, आकाश की ओर यह दिशा बतलाता है और समय

बतलाता है कि रात के इतने बजे हैं और यह उत्तर तरफ है, उसी तरह यह सप्तनिश्चय सारे राज्य के लिए दिशा का परिचायक है और फलदायक है । मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस सपने को लेकर चले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं जो कार्यक्रम को लेकर चले हैं लेकिन वहां आपको पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है । अगर पूरा सहयोग मिलता तो हमारा बिहार जो एक बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, बढ़ता हुआ बिहार है, विकसित बिहार है आज जनमानस में जो यहां का चित्र उभरा है उसमें जो बाधक बनना चाह रहे हैं, उसे देखना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार के अंग माने जाते हैं । महोदय, आज बजट पास हो रहा है, सरकार विकास के लिए पैसा मांग रही है तो हमारे जो विरोधी हैं जो हमारे सरकार के अंग माने जाते हैं वे लोग हमारे हाउस से गायब हैं । ये किस बात का सबूत है, उन्हें कार्य में बाधा डालने के सिवा और अपनी बात मनवाने के सिवा उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं, कोई कार्यक्रम है ही नहीं । वे लोग एक वर्ष में एक दिन भी असेम्बली को ठीक से नहीं चलने दिया । यह जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उस पवित्र मंदिर में कभी टेबुल पर चढ़कर, कभी कुर्सी पर चढ़कर जो संविधान की आत्म की हत्या कराया है वह आज मर्यादा की बात करता है और संस्कृति की बात करता है। उसे याद है उसे सीखना चाहिए कांग्रेस से मर्यादा, कांग्रेस से संस्कृति सीखना चाहिए उन्हें महोदय, 1977 में जब हमलोग जे0पी0 आन्दोलन में विपक्ष में बैठे थे उस समय की प्रोसिडिंग निकाल कर देखा जाय हमारी क्या भूमिका रही है । संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली में यह महान देश है, इसका लोकतंत्र महान है, इसकी संसदीय प्रणाली महान है, इस संसदीय प्रणाली का अनुकरण दुनिया का अनेक देश करते हैं मगर हमारे देश के लोग जो गांधी जी की हत्या करने वाले है, वे आज हमारे देश के संविधान की हत्या करने में तुल गये हैं । उन्हें मैं सावधान करता हूँ, वह तिरंगा झंडा नहीं था हमारा संस्कार था, वह लहरा रहे थे हम संस्कार को मिटने नहीं देंगे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान करे जो नीतीश कुमार और लालू को अपमान करे उसे यह देश, यह हिन्दुस्तान कभी बर्दास्त नहीं कर सकता है । हमारे देश का जो भविष्य है उसको हम मटियामेट नहीं होने देंगे चाहे जो भी कठिनाई उत्पन्न हो । महोदय, टेबुल पर मैं चढ़ा हूं, क्या देखोगे, 2005 से 2010 तक का मेरा इतिहास देखो जब तुम सरकार में थे और मैं बैठा था विपक्ष में और उस समय अकेले सरकार के समर्थन में सहयोग देने के लिए उस पंक्ति में बैठा रहा । सारे डिमांड पर हमारे आते थे संशोधन और सरकार को मैं सहयोग करता था, स्वयं वित्त मंत्री उस समय मोदी जी थे, वे हमारे तरफ झांकते थे जरा सा बचा कर के काम कीजियेगा । आज उन्हें पता नहीं है रामदेव राय कहां बैठा हुआ है, पता नहीं है और उनको हम बचाकर चलते थे और आज वे डफली और राग बतला रहे हैं हमें मर्यादा सिखाते हैं । अगर हुजूर मैं टेबुल पर नहीं चढ़ता तो लोकतंत्र

की उस दिन हत्या होती, कितने लोग मारे जाते पता नहीं । मैं टेबुल पर चढ़कर इस संविधान की आत्मा की सुरक्षा किया है अगर ऐसा नहीं करता तो मैं भी मारा जाता मगर हुजूर, मैं कहूं अगर सारा हाउस माफ कर दे तो जब मैं देखा कि मैं बुरी तरह घिर गया हूँ तो मुझे अपनी शक्ति का एहसास जरा हो गया, हुजूर, पहले तो मैं अपने पैर से ठेलने का प्रयास किया, नहीं ठेलाया तो हाथ से एक बार ठेला तो गिर गया पूरा छितर बितर हो गया और मैं टेबुल पर चढ़कर उसकी रक्षा किया । अगर उस समय मैं रक्षा नहीं करता तो वह आदमी घायल हो जाता । वहां हमारे चेयर को देखना चाहिए उस समय चले गये थे नहीं तो सच्ची बात देखते और आज विपक्षी लोग मर्यादा की सीख देते हैं । महोदय, आज बजट भाषण हो रहा है तुम गायब हो जब जनता की आवाज यहां आती है, 2000 के नोट में मोबाईल का आवाज सुनता है, जनता की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, यह संविधान की आत्मा का हनन नहीं तो और क्या हो सकता है । संविधान में कहीं प्रावधान है कि 2000 के नोट में मोदी की आवाज सुनाई पड़े । उसके उभरे चिन्ह पर कोई आंकड़ा अंकित हों, कभी देखे हैं कभी इस देश का संविधान इसको कबूल किया । आज क्या है 2000 के नोट में जरा मोबाईल लगा दीजिये मोदी जी भाषण करते नजर आ जायेंगे । यह क्या है मखौल, इस देश का, इस देश के संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है इसे भारतवासी कभी बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। हमारे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद का जिस पर सोनिया गांधी और राहुल का आर्शीवाद है वह कभी पीछे नहीं हट सकता है, उसका हम सैनिक है जान देकर भी बिहार की गरिमा की रक्षा करेंगे, बिहार की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करेंगे, मर्यादा सीखने वाले को मर्यादा सिखायेंगे और उन्हें बतलायेंगे कि पहले किताब पढ़ो और देखो कि हमारा चरित्र क्या रहा है और तुम्हारा चरित्र क्या है.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य,आपका दो मिनट मात्र समय बचा है ।

श्री रामदेव राय: महोदय, ग्रामीण विकास उसी का एक चिन्ह है, इन्दिरा आवास का पैसा नहीं, सड़क बनाने का पैसा नहीं, शौचालय बनाने का पैसा नहीं और बैंक में जब पैसा निकासी के लिए जायेंगे तो कहेगा कि आज 2000 ही ए0टी0एम0 से निकलेगा । बतला दीजिये हुजूर, हमारा देश पूरा परेशान है परेशान हो रहे हैं हमारे मजदूर किसान, फिर बिहार को नीतीश कुमार कैसे उबार सकते हैं और फिर रामदेव राय कैसे पीछे रह सकता है आखिर हमें भी तो देखना होगा, हमको भी तो धमनियों में खून है, हम इन धमनियों के खून को बेकार नहीं जाने देंगे । हमने कुर्बानी दी है देश के लिए तो हम कुर्बानी देंगे बिहार के विकास के लिए इसकी रक्षा के लिए , लालू यादव के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद करने के लिए इसे कोई रोक नहीं सकता है । हम कानून के अधीन है हम उसका पालन करेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे और तुमको भी करना होगा नहीं तो जबरन तुमको करायेंगे नहीं तो हाउस में कभी नहीं

आने देंगे चाहे इसके लिए जो हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता था सफाई का वक्त, सफाई का वक्त मिला नहीं इसलिए अपना समय ग्रामीण विकास में दे दिया । मैं श्रवण कुमार जी से आग्रह करता हूँ, हमारे पहले वित्त मंत्री जी विजेन्द्र बाबू रहे हैं लगातार हमने विनती की आप देख लीजिये ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब एक मिनट समय बचा है ।

श्री रामदेव राय: हमने तो पहले ही कहा, जब आप कुर्सी पर आते हैं तो हमारा रूह कांपने लगता है । मैं हुजूर बतलाना चाहता हूँ । हुजूर, लगातार देख लीजिये 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 487316 करोड़ रू0 अनुमानित है जो भारत सरकार द्वारा सूचना के आधार पर है वहीं योजना विकास विभाग के पत्र के द्वारा 2015 के लिए 559808.65 करोड़ रू0 अनुमानित है इससे जी0डी0पी0 26 गुना हमारा ज्यादा बढ़ा है यह बिहार के विकास का नीतीश कुमार का सदन का लालू प्रसाद के सहयोग का कांग्रेस का सहयोग का ये प्रमाण है । (क्रमश:)

टर्न-11/मधुप/01.12.2016

..क्रमश:...

श्री रामदेव राय : इसलिये इस प्रमाण को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है । मैंने कहा हुजूर, प्रमाण प्रमाण है और इस प्रमाण के आधार पर बिहार का विकास होगा । बिहार का सात निश्चय जो है, शराबबंदी के बारे में कहना चाहता हूँ कि है दुनिया का कोई ऐसा देश चीन को छोड़कर जो इस कदम को उठाया हो ? कहाँ से आया नीतीश जी के माइंड में यह बात ? मैं समझता नहीं । महागठबंधन को धन्यवाद है कि नीतीश जी के कदम से कदम मिलाकर शराबबंदी को पूरा करने के लिये आज बिहार के गाँव के स्तर पर एक अभियान छेड़ दिया गया है । गाँव के नौजवान खुश हैं, माता और बहन खुश हैं, किसान-मजदूर खुश हैं, सारे तबके के लोग खुश हैं । हुजूर, बेटा घर में रात को पीकर आता था, माँ को पीटता था, बहू को पीटता था । आज माँ और बहु सुरक्षित है । बेटी स्कूल जाती है, कोई आज रोकने-टोकने वाला नहीं है । यह एक दार्शनिक विचार है । हुजूर, एक अध्याय बदला है । महोदय, धर्म का दो रूप होता है - एक पाखंड और दूसरा अध्यात्म । अध्यात्म के अनुयायी हमलोग हैं और पाखंड के अनुयायी वे लोग हैं जो राम-राम जपते हैं और पराया धन अपना करते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : एक-दो मिनट और समय नहीं देंगे, हुजूर ? (व्यवधान) हम कहना चाहते हैं कि निंदक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय, बिन पानी-साबुन के निर्मल करे सुहाय । आप तो निंदक हैं नहीं इसलिये मन कम लगता है ।

आज उनकी सारी तैयारी फेल हो गई श्रीमान्, मैं इतना ही जानता हूँ कि उनको त्याग-पत्र देना चाहिये । 2012-13 में बिहार 14.25 और देश 13.91, 2013-14 में 12.30 बिहार और देश 13.28, 2014-15 में बिहार 17.92 और देश का 10.78 विकास दर है । आज 2015-16 में बिहार 10.59 और देश 8.71 का है । उनको तो त्याग-पत्र देना चाहिये । बिहार जहाँ खनिज पदार्थ भी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है, नदियाँ भी सूखी हैं, गंगा भी रूठी है, हमारा पेट भी भूखा है, इसके बावजूद भी हमारी गठबंधन की सरकार बिहार के प्रयास से राज्य को विकसित बिहार बनाने के लिये जो काम किया गया है, यह एक प्रमाण है । इसलिये भारत सरकार को, मोदी सरकार को और उनके अनुयायियों को सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा कि यह भारत देश है, यह जब जगेगा तो छोड़ेगा नहीं । आप नोट में बोलिये चाहे चोट से बोलिये, हम चोट से बोलाने के लिये तैयार हैं, तुम्हारा नोट पड़ा रह जायेगा..

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रामदेव राय : महोदय, आपके आदेश का पालन करता हूँ । फिर कभी मौका मिलेगा तो अपनी बात कहूँगा । इन्हीं शब्दों के साथ ग्रामीण विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद, महागठबंधन को बहुत धन्यवाद, कांग्रेस को भी बहुत-बहुत धन्यवाद । चूंकि बिहार का विकास करने के लिये ग्रामीण विकास विभाग के जरिये आगे बढ़े हैं, इसलिये इसको भी धन्यवाद । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य,श्री सीताराम यादव ।

श्री सीताराम यादव : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग पर जो सप्लीमेंटरी माँग है, उसपर बोलने के लिये आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । आज बिहार के विकास का सवाल है, हमारे प्रतिपक्ष के साथी हाउस का बहिष्कार कर रहे हैं चूंकि वे सुन रहे थे कि सरकार का जय-जयकार होगा, चूंकि सारे क्षेत्रों में सभी तरफ विकास की गंगा बह रही है और सुनेंगे तो उनका छाती फट जायेगा । वे सुन नहीं सकते हैं । इसीलिये चुपचाप जाकर कहीं बिल में दुबक गये हैं ।

महोदय, भारत गाँवों का देश है और बिहार खासकर गाँव का देश है, न कोई इंडस्ट्री, न कोई फैक्ट्री, न कोई कल-कारखाना, केन्द्र का सौतेला व्यवहार, फिर भी अपने सीमित संसाधन से महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री उसमें ग्रामीण कार्य विभाग भी है और श्रवण बाबू भी हैं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि इन विभागों ने जो काम शुरूआत किया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सात निश्चय लाकर सभी क्षेत्रों को जो छूने का काम किया है जिसमें बिहार का जो विकास होने जा रहा है, जो काम होने जा रहा है, हमलोग हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं । सात

निश्चय इसमें आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली–नालियॉं, शौचालय निर्माण, अवसर बढ़े आगे पढ़ें, ये तमाम कार्य किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है । आर्थिक हल, युवाओं को बल, युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आपने जो कार्यक्रम रखा है, महोदय, किसी से छिपी हुई बातें नहीं हैं । आज तमाम लोग, हम गॉंव में रहते हैं, गॉंव में जाते हैं, तमाम जगह नीतीश कुमार के सात निश्चय की चर्चा होती है, चौक पर, चौराहे पर, बस स्टैंड में, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर सबलोग समझने लगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सात निश्चय जो बनाया है जिसमें सारे पहलू को छूने का काम किया गया है, महिला का विकास, युवाओं का विकास, हर घर सड़क, नाली–गलियॉं बन जायं तो ये भाजपा के लोग जो रामराज की परिकल्पना करते हैं, सचमुच में यह जो सात निश्चय है महोदय, जब पूर्णतः लागू हो जायेगा तो 5 वर्ष में बिहार देश का नहीं बल्कि दुनिया का एक नमूना बन जायेगा । मैं दावे के साथ इस बात को रखना चाहता हूँ ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शिक्षा के तरफ जो ध्यान दिये, हमारी लड़कियॉं अशिक्षित रहती थी, पढ़ने स्कूल में नहीं जाती थी, पोशाक योजना, साइकिल योजना, पुस्तक, स्टाइपेन, सारी चीजों से लैस करके उनको पाठशाला जाने के लिये, विद्यालय जाने के जो उत्प्रेरित किया है इन्होंने, जब हमलोग सड़क पर चलते हैं तो लड़की अपने पोशाक में साइकिल पर चढ़कर जब सड़क पर स्कूल–आवर में जाती है तो देखने में जो दृश्य रहता है, मैं उसकी चर्चा और उसका बखान अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ । वह चलती हैं झुंड में, सौ–सौ लड़कियॉं एक साथ गॉंव से साइकिल पर चढ़कर जा रही हैं, एक दृश्य देखने में लगता है, इतना बढ़िया देखने में लगता है । सब घर की लड़की अब पढ़ने लगी है चूंकि उन्होंने देखा कि शिक्षकों की बहाली हुई, महिलाओं को आरक्षण मिला, महिला गॉंव की मुखिया हो रही हैं, पंचायत समिति की सदस्या हो रही हैं, प्रखंड में प्रमुख हो रही हैं, जिला परिषद की सदस्या हो रही हैं, जिला परिषद की अध्यक्षा हो रही हैं । जो समाज उपेक्षित, जो तबका गॉंव का उपेक्षित जिसने कभी पंचायत का नहीं, वार्ड का भी नहीं अगुवाई किया, वह महिला आज गॉंव की मुखिया और सरपंच कुर्सी लगाकर कोर्ट लगाती हैं, प्रखंड में डोमिनी देवी, फेकनी देवी प्रमुख होती हैं । जो कभी बाबू लोग, पैसे वाले भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जो लोग हैं, वैसे लोगों का प्रखंड पर कब्जा होता था, वैसे लोग प्रखंड पर कुर्सी लगाते थे और आज गॉंव की डोमिनी देवी, फेकनी देवी, छूतहर सदा, मुसहर राम प्रखंड के प्रमुख हो रहे हैं, फेकन सहनी प्रमुख हो रहे हैं । गॉंव में एक गरीब घर की एक दलित समाज की महिला 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करती हैं और बाबू लोग प्रसाद के लिये खड़े रहते हैं । उनको देखना पड़ता है, छाती फट रहा है भाजपा के

भाइयों को, वे देख नहीं सकते, वे सुन नहीं सकते, नीतीश कुमार ने गॉव की डोमिनी और फेकनी को इतना अधिकार दे दिया, इतना सम्मान दे दिया ? हम पांत में खड़ा हैं और वह झंडोत्तोलन कर रही है ? जो कभी प्रसाद के लिये टकटकी निगाह से खड़ी रहती थी, आज वह झंडोत्तोलन करती हैं, आज वह गॉव की मुखिया बनी है । यह देन है महागठबंधन की सरकार का और नीतीश कुमार जी का, ग्रामीण विकास मंत्री का यह जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, यह भाजपा के लोग कैसे देखेंगे ?

....क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/01.12.2016

श्री सीताराम यादव : (क्रमशः) महिलाओं के लिए आज महिला थाना खुला है, महिला बटालियन खुला है । पुलिस, सब इन्सपेक्टर आज महिला होती है, कॉन्सटेबुल आज महिला होती है। महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, नारी कल्याण, नारी उत्थान और नारी सशक्तिकरण का जो अभियान हमारे बिहार सरकार का है, काबिले तारीफ है । मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि तुम जीयो हजारों साल कि हर दिन के हो पचास हजार, यह मेरी है आरजू, श्री नीतीश कुमार जी, तुमको कोटि-कोटि धन्यवाद । लालू प्रसाद यादव जी, तुमको कोटि-कोटि धन्यवाद, सोनिया गॉधी जी, कोटि-कोटि धन्यवाद । सारे मन के भेद को मिटा करके भाजपा को रोकने का काम जो आपलोगों ने, इन तीनों नेताओं ने किया है । ये दंगा-फसाद करने वाली पार्टी है और यह बिहार में ही नहीं, यह पार्टी हिन्दुस्तान में दंगा लगा करके, मंदिर-मस्जिद का झगड़ा लगा करके सत्ता के कुर्सी पर काबिज हो गई है । ये झुठ का पुलिन्दा बांट रहे हैं । आज सारे जगह रोका, इन्होंने समस्तीपुर में रोका आडवाणी जी को.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका मात्र 2 मिनट समय है ।

श्री सीताराम यादव : इस बार बिहार में रोका और नीतीश कुमार जी को बिहार में बैठाया और भाजपा के सुशील मोदी जी, जो मन बना करके रखे थे, उनका सपना चूर-चूर हो गया, इसके लिए हम तीनों नेताओं को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ । महोदय, हमको एक-दो मिनट का समय दिया जाय .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास दो मिनट का वक्त है ।

श्री सीताराम यादव : ठीक है । बहुत,बहुत धन्यवाद । आज हम एक चीज कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि हर घर तक पक्की गली, नाली, शौचालय का निर्माण, इन्होंने सबसे बड़ा कार्यक्रम शौचालय के लिए बनाया है और इसमें हम एक चीज कहेंगे माननीय मंत्री जी से कि थोड़ा सा इसपर ध्यान रखा जाय । हमारे प्रखंड में जब कोई भी योजना चलती है तब ब्यूरोक्रेट्स में कुछ लोग बैठे होते हैं, जिनकी गिद्ध दृष्टि उधर चली जाती है कि इसमें से किस तरह से निकाला जायेगा, इसमें किस तरह से कमीशनखोरी होगी ? तैयारी

चल रहा है, चूँकि हमलोग गांव में रहते हैं, इसलिए आपने जो योजना बनायी है, उसका पैसा शतप्रतिशत गरीबों के हाथ में जाय और जमीन पर योजना बनायी जाय, शौचालय बने । कुछ बड़े लोग पहले का बनाये हुए शौचालय है, उसी का फोटो खिंचवाकर पैसा हड़पना चाह रहे हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, ऐसा नहीं हो कि हमलोग पहरेदारी करते रहे, देखते रहें और सरकार की भी आँखें उसपर लगी रहे । अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से, मैं आग्रह करूँगा ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री शैलेश बाबू से कि हम जहां से आते हैं , वहां कमला नदी है और कमला नदी के अन्दर बहुत सारी बस्तियां बसी हुई है और वह दियर में है । दोनों तटबंध उसका बायां और दायां है। दोनों पर ईट सोलिंग बहुत पहले हुआ, ईट उखड़ गया है, रास्ते चलने में बड़ी कइिनाई होती है । माननीय मुख्यमंत्री जी का जब कमीश्नरी वाला प्रोग्राम हुआ था तो दरभंगा में कमला नदी के दोनों तटबंध को पक्कीकरण कराने के संबंध में हमने लिखवाया था, यहां से गया है जिला को, उसका कागजात भी बनकर आ गया है । मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि कमला नदी के दोनों तटबंध का पूर्ण रूप से पक्कीकरण किया जाय । जो गांव वर्षों-वर्ष से, सैंकड़ों वर्ष से, हजारों वर्षों से कच्ची है, उस गांव को पक्की सड़क नसीब होगा महोदय.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री सीताराम यादव : यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि किंग्स कमला नहर है, उसका जो सर्विस रोड है, उसका भी पक्कीकरण किया जाय, यह मैं इस सरकार से मांग करता हूँ। दूसरी तरफ ये जो बात कह रहे हैं, अभी मौसम है रब्बी बोने का, ये नोटबंदी लगा करके .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, थोड़ा सा समय दिया जाय । ये नोटबंदी लगा करके हमलोग कहां से खाद खरीदेंगे, कहां से हमलोग बीज खरीदेंगे, कहां ट्रैक्टर से जोताई होगी, धान की दौनी कैसे होगी ? यह तमाम सवाल उठा करके इन्होंने खड़ा कर दिया है । ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं । गांव में रहने वाले जो लोग हैं,उनको ये सताना चाहते हैं । अभी दो रूपया दूध पर दाम बढ़ा है । कल रात टी0वी0 पर देख रहे थे, इनके जो एम0एल0सी0 बने हैं श्री विनोद नारायण झा जी, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, वे कह रहे हैं कि जुल्म हो गया, गजब हो गया । दूध पर 2 रूपया बढ़ गया, जहां सोना 30 से 60 हो गया एक रात में विनोद नारायण झा जी, तुमको आँख में यह देखने के लिए रोशनी नहीं है और दूध पर 2 रूपया बढ़ा तो छाती पीट रहे हैं .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें ।

श्री सीताराम यादव : महोदय, ये छाती पीट रहे हैं । इससे किसानों को फायदा होने जा रहा है, कोई व्यापारी को फायदा नहीं होने जा रहा है सभापति महोदय । किसानों को 2 रू0 बढ़ा है। महोदय, आप बार-बार हमको नोटिश कर रहे हैं, बोलने का तो मन बहुत था लेकिन समय नहीं है । आपका भी तकादा हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महागठबंधन की सरकार को और हमारे बिजली मंत्री जी, जो गांवों को जगमगाये हैं, देखने में आज सारा गांव लगता है कि शहर से कम नहीं, इसलिए माननीय उर्जा मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ । हमारे नगर विकास मंत्री भी झांक रहे हैं, हमारे जयनगर में योजना दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ । इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत,बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ । महागठबंधन की सरकार, जिन्दाबाद-जिन्दाबाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2016-17 के अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत,बहुत आभार प्रकट करता हूँ । सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महागठबंधन की सरकार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार अपने चुनाव के दौरान जो वायदे किये थे, हरेक 218 विधान में जाकर शराबबंदी और सात निश्चय का, उन्होंने आज उसको पूरा करने का काम किया है , मैं उनके प्रति हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ । आज 7 निश्चय का काम पूरा हो रहा है । हमारे गांव में, समाज में काम एक-दो जगह चालू कर दिया गया है । आज 7 निश्चय का काम पूरा होने से समुचा गांव को स्मार्ट बनने में देरी नहीं लगेगा । आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच गांव को स्मार्ट बनाने का है, जिसपर कि काम चल रहा है । आज भारत सरकार, केन्द्र सरकार का प्रधानमंत्री जी का सोच शहर को स्मार्ट बनाने का है, जो शहर पूर्व से ही स्मार्ट बना हुआ है । बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शराबबंदी जो लागू किया गया है, उसका सबसे पहला कार्यक्रम है, मैं उसपर हार्दिक धन्यवाद देता हूँ महागठबंधन सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आज शराबबंदी जिस दिन से लागू हुआ, खास करके हमारे महिला समाज में खुशियां फैली, आज महिला समाज उत्सव मनाने का काम किये हैं कि त्योहार की तरह खुशियां मनाने का काम किये । आज हमारे गांव, समाज में शांति व्यवस्था फैली हुई है, उसका मुख्य कारण है शराबबंदी, जिसमें कि हर दिन शाम के समय जब लोग बाजार से आते थे तो गांव में हलचल होता था 12 बजे रात तक, जबकि आज गांव में घुमने से गांव में खुशहाली का

माहौल है हरेक घर में । जो पति-पत्नी गांव में झगड़ा झंझट करते थे, आज दोनों पति-पत्नी एक जगह बैठ करके अपना प्रेमपूर्वक बातचीत करते हैं । आज रोड एक्सीडेंट घट गया है । आज अभी-अभी जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज चुनाव का खर्चा बहुत बच गया है सभी कैंडीडेट का, आज उसका देन है शराबबंदी । आज महागठबंधन सरकार का देन है, आज शराबबंदी से हमारे हरेक परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जो पैसे बर्बादी की जगह जाते थे, वह आज हरेक घर में पैसा बच रहा है और आज उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है हरेक परिवार में, गांव में और समाज में । आज शराबबंदी का वह असर है, जिसपर कि हमारे शराबबंदी पर, हमारे विपक्ष के लोग बहुत सा वाद-विवाद किये लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अडिग हैं और अडिग रहेंगे और हमलोग उनके सहमति के लिए महागठबंधन की सरकार, हमलोग उनके साथ हैं, इसके लिए उनको कुछ सोचने की बात नहीं है । अभी-अभी माननीय सदस्य बता रहे थे मान-सम्मान की बात, आज मान-सम्मान जिनके द्वारा दिया जा रहा है, खासकर के महादलित परिवार को झंडातोलन का काम उनके द्वारा हो रहा है, इनके बगल में अनुमंडल पदाधिकारी विराजमान रहते हैं और वहां पर के बहुत से लोगों का छाती फटता है, उनके सम्मान को देखकर । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महागठबंधन सरकार की ही आज यह देन है । बहुत से ऐसा कार्यक्रम होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बताते हैं कि 7 निश्चय को पूरा होने के बाद आपलोगों को भी अगला चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन आपलोग अग्रसर होकर अपने क्षेत्र में काम कीजिए और सही में 7 निश्चय पूरा होगा तो हमारा गांव, समाज स्मार्ट गांव बनकर रहेगा, इसमें कतई दो मत नहीं है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-13/अंजनी/दि0 01.12.2016

श्री निरंजन कुमार मेहता .....क्रमशः.....

महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा चल रही है, उसपर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार राज्य के विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है । राज्य सरकार की योजनायें राज्य में अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से बनायी जाती है तथा इन सबका कार्यान्वयन भी गंभीर तरीके से सरकार अपने नियंत्रण एवं निर्देशन में करा रही है, जिसका प्रत्यक्षतः लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है । ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हो रही है । ग्रामीण विकास विभाग का जो मुख्य काम है- जैसे इंदिरा आवास, उस इंदिरा आवास के नाम को चेंज कर दिया गया

है केन्द्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा । अब उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना । समाज के बेघर मकानविहीन लोगों को इंदिरा आवास जिसे प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण) के रूप में जानते हैं, को मकान उपलब्ध कराने की सतत् कार्रवाई चल रही है । हमारा राज्य भारतवर्ष में आवास पूर्ण के मामले में दूसरे स्थान पर है । नवम्बर माह में तीसरे सप्ताह तक कुल पूर्ण किये गये आवासों की कुल संख्या वर्ष 2016-17 में 3,10,543 है । सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास हरेक प्रखंड के पंचायत में लक्ष्य के अनुसार पूर्णतः लागू हो, इसका प्रयास किया जा रहा है । पूर्व में ही आवास सहायक का नियोजन भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया गया है । अब वर्ष 2011 की आर्थिक, सामाजिक एवं जातीय जनगणना के आधार पर लाभुकों को सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास दी जा रही है । प्रधानमंत्री आवास योजना पर हरेक जिला के प्रखंड द्वारा पंचायतों में पूरी तत्परता के साथ लक्ष्य के अनुसार काम किया जा रहा है, जिससे कि समयानुसार पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जा सके । इस संबंध में सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बराबर इसकी समीक्षा की जा रही है, इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय, मनरेगा, महात्मा गांधी एक मांग आधारित कार्यक्रम है, जिसका शासन एवं क्रियान्वयन तंत्र "काम की मांग के पंजीयन" से प्रेरित होता है । ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी परिवार के व्यस्क सदस्य द्वारा आवेदन देकर जॉब कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें उसे काम के मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक सौ दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, अर्थात् यह सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर आधारित समावेशी विकास का यह एक सशक्त माध्यम है । मजदूरों के भुगतान को प्रभावशाली बनाने के लिए एन0ई0एम0एम0एस0 प्रणाली लागू कर मजदूरों के खाते में सीधे निधि के अन्तरण की व्यवस्था विभाग द्वारा की गयी है । कभी-कभी केन्द्र सरकार द्वारा निधियों में विलम्ब होता है तो कामगारों को मजदूरी भुगतान के लिए परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गयी है हमारी सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, जिससे जॉब कार्डधारी कामगारों को भुगतान में कोई समस्या उपलब्ध नहीं हो । केन्द्र सरकार के द्वारा मात्र 167 रूपया ही मजदूरी निर्धारित है, किन्तु राज्य सरकार अपने संसाधन से 10 रूपया अतिरिक्त जोड़कर 177 रूपया प्रति कार्य दिवस मजदूरी भुगतान कर रही है । यह एक मांग आधारित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में अत्यंत निर्धन और सीमांत व्यक्तियों को रोजगार मिलता है । इस योजना में कार्यों की 16 श्रेणियां हैं । जल संरक्षण, वनरोपण, लघु सिंचाई सहित सिंचाई नहरें सिंचाई सुविधा, खेत में बनाये गये तालाब, बागवानी, पौधारोपण, खेत बांध बनाना, भूमि विकास का प्रावधान, तालाबों से गाद

निकालने सहित पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, सड़क सम्पर्कता, कृषि संबंधी कार्य, पशुधन संबंधी कार्य, मत्स्यपालन, ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य, ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य । मनरेगा में उपरोक्त सभी कार्य किसान पर आधारित है....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपके पास मात्र एक मिनट समय है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : तथा सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत के द्वारा इतने सभी कार्यों का संचालन हो रहा है । अभी-अभी कुछ दिनों पहले ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा पत्रांक 1349 दिनांक 26.08.2016 के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें सभी माननीय सदस्य मनरेगा से संबंधित कोई कार्य अपने क्षेत्र में कराने के लिए जिला उप विकास आयुक्त को पत्र मिला था । जिसके फलस्वरूप हमलोग अपने क्षेत्र में काम किये हैं । मनरेगा में बांध पर रोपण और तालाब का काम हरेक क्षेत्र में हो रहा है । सड़क के किनारे, सरकारी संस्थान में मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण का काम हो रहा है । अब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो रही है और प्रत्येक प्रखंड के दो पंचायत में लोहिया स्वच्छ योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके होने से स्वच्छमुक्त वातावरण हो जायेगा हमारे ग्राम पंचायत में ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । महोदय, एक जीविका है, जीविका भी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है । जीविका एक ऐसा सशक्तपूर्ण संगठन है, जो हमारी महिला समाज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि 35 परसेंट महिला को आरक्षण दिया गया है, उसमें जीविका में हमारी महिला समूह काम कर रही हैं । जो परिवार आज जीविका से जुड़े हुए हैं, उनको गांव में किसी का मुहताज नहीं होना पड़ता है । वह अपने परिवार का काम करे या कोई बिजनेस करे, यह भी हमारे महागठबंधन सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है । इन्हीं शब्दों के साथ महागठबंधन सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया अनुपूरक बजट पर, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी । आपके पास पांच मिनट समय है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग पर आपने जो बोलने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं तो जेल से आता हूँ, बहुत सारी तैयारियां हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आज भाषण देने के पक्ष में नहीं

हूँ । अपने विधान सभा क्षेत्र की जो मूल-मूल समस्यायें हैं, उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । मैं मांग करना चाहता हूँ कि सरकार उन समस्याओं का समाधान करे । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि दरौली प्रखंड के, दरौली विधान सभा के दरौली प्रखंड के ग्राम सहजनिया में, सहजनिया एक गांव है, छोटा ही है जो सिर्फ महादलित लोगों का है । ये लोग मेहनत, मजदूरी करके, श्रम करके अपनी जीविका चलाते हैं । एक नंद नारायण राम थे, जो गोशाला में बगल का गांव है एकसरहरवा गांव है, जो बाबू लोगों का गांव है, वहां के बाबू साहेब के गोशाला में गोबर उठाते थे, मवेशियों को खिलाते थे, मेहनत करते थे । महोदय, जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मजदूरी मांगी, मजदूरी मांगने के चलते दिनांक 8.7.2015 की रात में नंद नारायण राम की हत्या कर दी गयी, गोली मारकर हत्या कर दी गयी और खुद दूसरे पर, जिसने गोली मारी थी वही आदमी दूसरे आदमी पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दिया । लेकिन जब हमलोगों ने उसकी तहकीकात की तो नंद नारायण राम का लड़का राजू राम ने बताया कि हम गये थे पैसा मांगने के लिए, हमारी मां की तबीयत खराब थी ...

....क्रमशः.....

टर्न-14/शंभु/01.12.16

श्री सत्यदेव राम : क्रमशः.....और पैसे मांगते वक्त ही उन्होंने कहा है कि ठीक है, आज रात में हम मजदूरी दे देंगे। महोदय, जॉच पड़ताल हुई तो पता चला कि इनके उपर तो एफ0आइ0आर0 दर्ज हुआ। लेकिन आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, वे थाने और औफिसों में जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही मृत नन्द नारायण राम के पीड़ित परिजनों को आज तक कोई मुआवजा भी नहीं मिला है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मृत नन्द नारायण राम के पीड़ित परिवार को 7 लाख रूपया देने की मांग करता हूँ। महोदय, दरौली प्रखंड के ही एक बिढ़नी गांव है जिस गांव की कहानी समाप्त हो चुकी है, चूंकि जब वह गांव था- आज वह नदी बन गया है, आज वह गांव नहीं रह गया- 50 से ऊपर महादलित लोग नदी के तटबंध पर अपनी जीविका, अपना जीवन यापन करते हैं। वे झोपड़ी डालकर वहां अपना जीवन बसर करते हैं और छोटी-छोटी नावें जिसको वे लोग डेंगी कहते हैं- उस नाव से वे लोग नदी पारकर के दीयर से अपनी जीविका के सारे साधन जुटाते हैं और उसी से मछली मारते हैं और वही उनकी जीविका का साधन है। इसी 26 तारीख को महिलाएं उस नौका से लकड़ी चुनने उस पार जा रही थी, बीच सरयू नदी में वह नौका डूब गयी और तीन महिलाओं की डूबकर मौत हो गयी। दो दिन के बाद एक लाश मिली है बाकी

लापता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब अन्य हादसों में 4 लाख रूपया दिया जा सकता है तो बिढ़नी के महादलितों को, गरीब भूमिहीनों को भी 4 लाख रूपया देने की मैं मांग करता हूँ। महोदय, दरौली विधान सभा क्षेत्र का ही गुठनी प्रखंड है- गुठनी प्रखंड में लोक मान्य तिलक विद्यालय जो सर्वप्रथम उच्च विद्यालय बना था, लेकिन महोदय आज उन सुदूर इलाकों में- वह यू0पी0 का बार्डर है, सुदूर इलाका है, लेकिन उन सुदूर इलाके के बच्चों को दो शिफ्ट में पढ़ाई करनी पड़ती है। उस विद्यालय में 1600 बच्चे और बच्चियां है, लेकिन भवन का अभाव है- कायदे से आज उस उच्च विद्यालय को कम से कम 10 रूम चाहिए। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी बातों की नोटिस होनी चाहिए और इस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए- लोक मान्य तिलक उच्च विद्यालय, गुठनी, सीवान का पक्का 10 रूम बनाने की कृपा करनी चाहिए। महोदय, हम इसी सदन में बजट सत्र में भी अपनी बात को रखे थे।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपका समय हो गया है सत्यदेव बाबू।

श्री सत्यदेव राम : पी0डब्लू0डी0 मंत्री महोदय से भी आग्रह किया था.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आसन ग्रहण कीजिए।

श्री सत्यदेव राम : मेरे क्षेत्र में आंदर प्रखंड है और उस आंदर प्रखंड में एक रोड जो ग्रामीण सड़क है.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, समाप्त कर रहा हूँ। दीयर से अंदर तक ग्रामीण सड़क है। हमने कई माध्यमों से मांग किया कि इस सड़क को पी0डब्लू0डी0 से जोड़ दिया जाय। हम इतना ही मांग किये हैं और आज फिर मैं मांग करता हूँ कि हमारी इस मांग को सुना जाय और उस सड़क को पी0डब्लू0डी0 से जोड़ दिया जाय। महोदय, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरयू नदी में एक पुल भागलपुर है और एक छपरा है, बीच में सरयू नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। सिकन्दरपुर और दरौली दोनों करीब के बाजार हैं, अच्छे खासे बाजार हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि दरौली थाना जो है, वह एक ऐसा थाना है कि वह कभी आज के 24 थानों के बराबर था और आज उसमें 24 थाने बने हैं। आज वहां की पूरी जनता किसान, मजदूर की मांग है कि सरयू नदी में दरौली के सामने सरयू नदी में एक पुल का निर्माण हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरयू नदी में पुल के निर्माण का काम पूरा करें।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आसन ग्रहण कीजिए।

श्री सत्यदेव राम : इसी के साथ हम आशा करते हैं कि हमने अपने क्षेत्र के जिन सवालों को सरकार के सामने रखा है- जरूर सभी मंत्री उपस्थित नहीं हैं, रहना चाहिए था इसलिए कि आज भर ही अपनी बात कहने का अवसर है, मौका है, फिर कल हम कोई बात नहीं कर पायेंगे। इसलिए हम सारे विभागों के सवालों पर अपने क्षेत्र से जुड़े सवालों पर

बात रखे हैं, हमारी नोटिस जानी चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : सभापति महोदय जी, ग्रामीण मंत्री हमारे श्रवण जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : यहां सभी माननीय सदस्यगण हैं।

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : माननीय सदस्यगण, आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका मिला है, मैं सदन को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। ग्रामीण विकास में अच्छा काम होता है, लेकिन मैं कुछ समस्याएं भी बताऊंगा- समस्या यह है कि हमारे क्षेत्र में गांवों में जो शौचालय बनता है तो शौचालय में गरीब गुरबा के हाथ में पैसा नहीं है तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जैसे पहले इंदिरा आवास बनता था, अभी प्रधानमंत्री आवास हो गया है, उसमें जैसे पहले एडवांस मिलता था वैसे ही इसमें भी एडवांस मिले तो विकास जल्दी जल्दी होगा। हम पहले सवाल उठाये थे बी0पी0एल0 वाला, जब हमारे गरीब गुरबा का नाम बी0पी0एल0 में नहीं था और हमारे जिला से नाम लिखकर जाता है कि उसी का घर बनना चाहिए- अब इसमें समस्या है कि गरीब लोगों से पहले धनिक लोगों का बी0पी0एल0 में नाम है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। 300 लोगों का बनाना है और उसमें 300-400 जाता है, उसमें से छांटकर उसी में बनाना है तो हम मंत्री जी से कहेंगे कि जो बी0पी0एल0 में नाम छूट गया है उसमें जोड़ना जरूरी है। उसमें जो पदाधिकारी है वे जाकर पहचानकर नाम भेजें, ऐसे मुखिया लोगों को ड्यूटी मिला है, बी0डी0ओ0 को ड्यूटी मिला है कि उसी में से पहचानकर बनाना है। ये ऐसी-ऐसी समस्या है कि 200 नहीं 150 बनाना है तो उसी में से बनाना है। हम ग्रामीण मंत्री जी से कहेंगे कि इसमें सुधार लाया जाय, चूंकि बहुत अच्छा काम है। सात निश्चय का काम है- माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लालू जी, तेजप्रताप जी, तेजस्वी जी, सोनिया जी ये हमारे महागठबंधन का निर्णय है। इस गठबंधन के निर्णय से भाजपा के लोगों में घबड़ाहट है। जिस राजा के राज में प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं होता है, सुनने का अधिकार नहीं होता है, वैसे ही इस सदन में भाजपा के लोग अपने मन से ही भाग गये। ये लोग कहे कि कुछ भाजपा के लिए भी बोलना है- हम देखे कि अपने मन से भाजपा वाले हल्ला किये, अपने से टेबुल उलट दिये, अपने से महिला के चुड़ी फोड़ दिये और इससे महिला को चोट भी लगी.....क्रमशः।

टर्न-15/अशोक/01.12.2016

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : क्रमशः.... हम माननीय प्रधान मंत्री से बोलेंगे कि वे अपने वाईफ को क्यों छोड़ दिये, अपने औरत को छोड़ दिये हैं इसलिए हम कहेंगे कि पहले महिला में यशोदा बेन को बुलाना चाहिए उनको, इसलिए कि वे

महिला के बारे में बोल रहें है । हम कहना चाहते हैं कि दूध का दाम बढ़ा है, यह बहुत ही अच्छा हुआ हैं, हमने दूध के बारे में घ्यानाकर्षण भी लाये थे। गरीब-गुरूबा गाय पालते हैं। माननीय मंत्री जी ने हमलोगों के दु:ख को सुनकर दूध का दाम दो रूपये बढ़ाया है, जो दूध का दाम बढ़ा हैं इससे उनलोगों को भी फायदा होगा। यह सुन कर अच्छा लगा कि दो रूपया प्रति लीटर दाम बढ़ गया है। शहर में तो लोग विलायती दूध पीते हैं । हमने कल पेपर में पढ़े कि दूध का दाम बढ़ गया है, इस तरह से जो दाम दूध का बढ़ा है इससे गरीब-गुरूबा को भी फायदा होगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी लोगों को पेंशन की समस्या है, आठ महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिला है, जब मीटिंग होती है तो पेंशन के बारे में अधिकारियों से बोलते हैं तो अधिकारी लोग बोलते हैं कि पेंशन अब आई, अब आई, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं मिलने से लोगों को परेशानी है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अधिकारियों से कह कर इसमें तेजी लाने की कार्रवाई की जाय । जिस तरह से श्रवणजी अपने माता-पिता को अपने कंधे पर ले तीर्थस्थान घुमाये उसी तरह से हम माननीय मंत्री श्रवण बाबू को बधाई देना चाहता हैं कि वे भी अपने कंधे पर तीन पार्टी को लेकर चल रहे हैं। मैं श्रवण बाबू को बधाई देता हूॅ और मैं उनसे कहना चाहता हूॅ कि गांव के गरीब-गुरूबा को दिक्कत है, नोट बन्दी के चलते गरीब-गुरूबा को दिक्कत है, नोट बन्दी के चलते लोगों की समस्या अटका हुआ है। लोगों को मजदूरी नहीं मिल रहा है, मिस्त्री को पैसा नहीं मिल रहा है । लोगों को गिट्टी ढोने के लिए काम नहीं मिल रहा है । जितनी मां बहनों की चोरी का पैसा था वह सब निकल गया । जो पूंजीपति लोग हैं उनको दिक्कत नहीं है । हम रात दिन लोगों को देखते हैं, एक दिन, एतवार के दिन हम कहीं नहीं जाते हैं, हम क्षेत्र में ही रहते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, नोट बंदी जो है वह ठीक है लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं उनको दिक्कत नहीं है, इससे गरीब जनता को काफी दु:ख है, परेशानी है, नोट बंदी के खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो लोग कहेगा कि इनके पास काफी पैसा है, इसलिए ज्यादा हमलोग नहीं बोल पाते हैं । डेली सुबह पटना चले आते हैं, बैंक में पैसा नहीं है, हमारे यहां ठाकुर भाई की बेटी की विवाह है, बैंक मैनेजर कहते हैं कि 25 हजार से ज्यादा नहीं देंगे, जो नौकरी करते हैं या जो रिटायर कर गये हैं उनकी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, ढाई लाख में क्यों होगा ? शादी में टी.वी. देना है तिलक चढ़ाना है, बाराती के खिलाने के लिए स्वागत के लिए पैसा चाहिए और पैसा रहते बैंक से पैसा नहीं मिल पा रहा है । भा.ज.पा. के लोग बहुत कूद रहे हैं लेकिन आने वाले

समय में जनता उनको बतला देगी । गांव-गांव में इतना न खलबली है, गांव के गरीब गुरूबा को तकलीफ है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, लालू जी के, तेज प्रताप जी के, तेजस्वी जी के, सोनिया जी के साथ जो गठबन्धन बना है, उससे जनता का काम हो रहा है, जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, या जो वार्ड है, इनके द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं वे बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहे हैं । ऊपर-ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है जो जमीन पर चलता है उसी से बड़ा पार होता है । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो महागठबन्धन के नेता हैं, वे जमीन के आदमी है, धरती के आदमी हैं, इससे बहुत ही फायदा है । हाफ पैंट पहन कर लोग घूमते हैं, हाफ पैंट तो लोग घर में पहनता है, हम तो पहले भी बोले थे कि जनता ने हमलोगों को चुन कर यहां भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, लेकिन लोग यहां हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करने का जगह यह नहीं है, यहां हल्ला करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो झूठी बात बोलना चाहते हैं वे ऊंची आवाज में बोलते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी जब गरीब गुरूबा के टोला में गये, पिछड़ा के टोला में गये, 15-20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ लालू जी को, जिनसे हमलोगों ने शांति महसूस किया है, जो लड़के बिगड़े हुये थे वे आज सुधर गये हैं । एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले एक महीना से होम डिलिवरी शुरू हो गया है, हम कहना चाहेंगे कि हमारे सारे अधिकारी हैं, मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब थाना लोगों को बतला दे रहे हैं कि पैसा लेकर के दारू बेचवाया जा रहा है । हम यह कहना चाहते हैं कि लोगों को हिदायत दे दिया जाय कि दारू बेचते पकड़ा गया तो उनके कि खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी । जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं उनके यहां होम डिलिवरी हो रहा हैं, बोर्डर पार कर यह कार्य किया जा रहा है, हमारे इलाका में यह बंद था लेकिन एक महीना से डिस्टर्ब हो गया है, जहां तहां लोग पीते हैं, मैं थाना को फोन भी किया हूँ तथा माननीय मुख्य मंत्री को लिखकर भी दिया हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपके पास एक मिनट का ही समय है ।

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : हम माननीय मंत्री जी को कहेंगे, भा.ज.पा. के लोगों को कहेंगे कि अगर विकास करना चाहते हैं तो अगर हमलोग मिल कर काम नहीं करेंगे तो जैसे बाप बैटा का तालमेल नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, हम नेताओं में भी यदि तालमेल नहीं रहेगा तो राज्य विकास नहीं करेगा, विधायक एवं मुख्यमंत्री जी का तालमेल नहीं रहेगा तो विकास नहीं होगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए ताल-मेल जरूरी है । भा.ज.पा. की आदत बहुत खराब है,

यादव के वोट के लिए नित्यानंद जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इनको बनाने से यादव का वोट लालूजी को छोड़कर किसी को मिलने वाला नहीं है । नित्यानंद जी को भा.ज.पा का कमान संभालने के लिए दिया हैं उससे क्या? आपने तो दिल्ली में भी बनाया, आम पार्टी से तो आपका खटिया खड़ा हो गया । एम.पी. का अगर चुनाव हो तो एम.पी. के चुनाव में मेरी उम्मीद है कि एक भी सीट नहीं आयेगा । हम पीछे में नहीं बोलते हैं, हम सामने में बोलते हैं लेकिन महोदय वे लोग भाग गये हैं ।

माननीय सभापति महोदय जी, एक मिनट का समय है, मैं माननीय श्रवण बाबू, जो हमारे मंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूॅ कि हमारे यहां शौचालय तो बन रहा है, लेकिन एक समस्या लोन का है, लोन कहां से लोग लेंगे, पैसा आयेगा तो वह खाता में जायेगा, फिर खाता से लेगा तो मैं कहना चाहता हूॅ कि एडभांस- हमारे यहां तीन-तीन वार्ड सात निश्चय में हो गया है, पंचायत तीन-तीन वार्ड सात निश्चय में डाला गया है, काम शुरू है, ढला रहा है, नाला ढला रहा है लेकिन ठीकेदार पेमेंट कहां से करेगा ? पेमेंट कैसे करेगा ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अरूण कुमार (192-संदेश) : तब हम सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय लालू जी, माननीय राबड़ी जी, सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण ।

श्रीमती अमिता भूषण : माननीय सभापति महोदय, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पेश किये गये अनुदान की मांग के पक्ष में बोलने में बोलने के लिये खड़ी हूॅ । महोदय, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दुहराता है । अगर इंसान इससे सबक नहीं ले तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, वर्त्तमान भी इसी परिस्थिति का उदाहरण है, एक फरमान से पूरा देश त्रासदी के दौर से गुजर रहा हैं, ईश्वर ही जानते हैं इससे मुक्ति मिलेगी या नहीं । महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है "भारत की आत्मा गांव में बसती है" आज उनकी आत्मा रो रही है। बिहार सरकार का प्रयास है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, स्मार्ट सिटी की जगह स्मार्ट विलेज बने, स्मार्ट कार्ड की जगह स्मार्ट विजन हो, स्मार्ट सोच हो, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो और इसके लिए महागठबंधन सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने सात निश्चय में विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल किया है यथा (1)आर्थिक हल, युवाओं को बल, (2) अवसर बढ़े,

आगे पढ़ें, (3)घर तक पक्की गली-नालियां, (4)हर घर बिजली लगातार, (5)हर घर-नल का जल, (6)शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, (7)आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार ।

इन सात निश्चयों के तहत कई काम किये जाने हैं जिन्हें मूर्त्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग सजग और तत्पर है । जिस प्रयास को लोगों ने विफलता का नमूना बनाने की कोशिश की थी ...क्रमशः

टर्न-16:ज्योति

01-12-2016 क्रमशः

श्रीमती अमिता भूषण : आज उनके ही मुंह पर तमाचा बनकर मुंह चिढ़ा रही है । कहते हैं कि किसी की परिस्थिति का मजाक या उपहास करना बहुत महंगा पड़ता है । महोदय, निर्मल मन से ही निर्मल भारत का विकास हो सकता है । इसके लिए निर्मल सोच भी जरुरी है जिसे महागठबंधन सरकार पूरी निष्ठा से कर रही है । दरअसल राष्ट्रपिता बापू के सपनों का भारत समृद्ध, सशक्त गांवों का निर्माण था । इसी दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पंचायतों को सशक्त कर ग्रामीण विकास की पृष्ठभूमि तैयार की थी । बाद के वर्षों में भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा कई योजनाओं की एक साथ शुरुआत की गयी । इनसे गांवों के विकास में गति प्राप्त हुई । महोदय, वर्ष 2016-17 में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कई महत्वाकाक्षी योजनाओं का आरम्भ हुआ है और गांव की अर्थव्यवस्था में इनसे अपेक्षित बदलाव आयेगा । निश्चित रुप से इन योजनाओं की सफलता वित्तीय प्रावधानों से जुड़ी है । ऐसे में यदि निधि की कमी से ग्रामीण विकास की गति में ठहराव आता है तो हम अपनी ही जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पायेंगे । मैं विशेष रुप से, सदन के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी लोग काम करें, खास कर घर घर शौचालय की जो योजना है, उसमें तकनीकी रुप से थोड़ी सुधार लाने की जरुरत है क्योंकि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनके लिए योजना तैयार कर रहे हैं उनको उसमें कहीं न कहीं परेशानी आ रही है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति, सदन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ । धन्यवाद, जय हिंद।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

(श्री लक्ष्मेश्वर राय,स0वि0स0 - अनुपस्थित)

माननीय सदस्य,श्री मेवालाल चौधरी ।

श्री मेवा लाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री गण, माननीय विधायक गण। महोदय, आज हम सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

महोदय, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास करने के सिद्धान्त पर खड़ी है और तत्पर है । जब महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार ने एक साझा कार्यक्रम बनाया और उस साझा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने, उन तमाम बिन्दुओं को नजर में रखा ताकि गांव में रहने वाले कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी वर्ग के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, उनको यह फायदा हो और फायदा के अनुसार हम जिस चीज की परिकल्पना कर रहे हैं, एक विकसित राज्य बनाने का और हम विकसित राज्य बना रहे हैं । हमारी जो नीति है, जो भी कार्यक्रम बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीशन मोड के रुप में बना है । मीशन मोड का मतलब होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा लक्ष्य भी निर्धारित है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा समय भी निर्धारित है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की यह जो सोच है, यह जो परिकल्पना है, यह सोच हमलोगों को एक विकसित राज्य बनाने की तरफ बढ़ रही है। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह जनजाति- अनुसूचित जाति की परियोजना हो, उस परियोजना को भी धरातल पर लाने के लिए नीति में सुधार हुआ है और उस नीति को लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे है और इन्हीं सारी नीतियो को एक साथ सम्मिलित कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जिस निश्चय की बात आम जनता के बीच में करते थे, आज वो निश्चय सात निश्चय के रुप में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जो गांव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं लोग, उनको मूलभूत सुविधा देने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। महोदय, शायद बिहार राज्य भारत वर्ष का एक ऐसा राज्य होगा जो उन तमाम लोगों के लिए - वैसे लोग जिनको किसी चीज में मूलभूत सुविधा से वंचित न रहना पड़े, उस पर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है । माननीय सभापति महोदय, हमारी शिक्षा की नीति की अगर बात करें चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो चाहे वो किसी तरह की शिक्षा हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हरेक गांव, हरेक प्रखण्ड, हरेक अनुमंडल में तकनीकी कॉलेज खोला जाय और हरेक कमीशनरी में विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो शायद इस सोच से हमारे यहाँ शिक्षा में जागृति होगी और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उन तमाम नौजवान को जिनके पास आर्थिक कमी होती थी, सभापति महोदय, बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि जिसतरह से सरकार ने अपने ऊपर गारन्टी लेकर हमारे तमाम उन विद्यार्थियों को जो पैसे से वंचित हो जाते थे, जो पढ़ने के लिए आगे नहीं जा पाते थे, उनके लिए ऋण का मुहैय्या कराया गया है वह भी बहुत ही कम इन्टरेस्ट रेट पर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार की जो परिकल्पना है, हमारी शिक्षा में बढ़ोत्तरी होगी । उसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी, वैसे गरीब तबके के विद्यार्थी जो 12वीं क्लास के बाद वो नहीं पढ़ पाये, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं

सहायता भत्ता दिया गया है जिससे विद्यार्थी अपनी नौकरी के लिए फार्म भर सके और फार्म भरके आगे बढ़ सके । सभापति महोदय, आज समाज में एक बहुत बड़ी लहर आयी है और यह लहर का एक ही मात्र कारण है मद्य निषेध कानून, जिसके कारण हर लोगों में खुशी का मौहौल है । हर लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं । तमाम मजदूर क्लास के लोग जो अपनी मजदूरी का आधे से अधिक पैसा शराब में बर्बाद कर देते थे आज उन पैसे का इस्तेमाल एक अच्छे काम में हो रहा है, एक ऐसा काम जिससे उनके बच्चे पढ़ रहे जिससे उनके बच्चे स्कूल जा रहे है, उनका पोशाक हो रहा है । आज हमलोग ग्रामीण विकास विभाग की बात कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, एक जीविका एक ऐसा कार्यक्रम है और जीविका के माध्यम से जो चीज समाज में एक परिवर्तन ला रही है, जो चेतना को जगा रही है, सबसे बड़ा काम जीविका के माध्यम से हो रही है हमारी दीदीयॉं हमारे हर लोगों को हर व्यक्ति को, चाहे वह औरत हो, चाहे वह मर्द हो उनकी चेतना को जगाने का काम कर रही है और जब उनमें चेतना जग जायेगी जब उनको समझदारी आ जायेगी समाज में हर तरह का विकास करने में सहूलियत होगी । एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो स्वयं सहायता भत्ता ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से चलाया जा रहा है सभापति महोदय, यह एक ऐसी संस्था का रुप धीरे धीरे लेते जा रही है कि लोगों में भेदभाव जो लोगों में जो थोड़ी बहुत मनमुटाव होती थी उस मनमुटाव के कारण यह भी समाप्त हो जायेगा । जिस माध्यम से गांव का विकास होना चाहिए जिस माध्यम से गांव के हरेक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए शायद स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प ग्रूप के थ्रू आगे बढ़ेंगे, हमारा जो स्वच्छता अभियान में हमारा कुछ सलाह और सुझाव होगा माननीय मंत्री जी को चूँकि स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रूप है, हमारे सोसायटी में बड़े स्ट्रौंग रुप से यह काम कर रहा है, बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, माननीय मंत्री महोदय, शायद जो शौचालय की बात की जा रही है जो शौचालय की जो हमलोग देख रहे हैं कि कंपलीट वो ओ0डी0एफ0 शायद हमलोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं अगर स्वयं सहायता के माध्यम से अगर उनको इसतरह का काम करने दिया जाय और सरकार उसकी गारन्टी ले कि उसका जो भी भुगतान हो वह समय पे भुगतान हो जाय तो शायद हमलोग जिस ओ0डीएफव0 की बात रहे हैं पूर्ण शौचालय की बात कर हैं, शायद उस शौचालय को भी पूरा कर लेंगे सभापति महोदय, एक सबसे अच्छी बात है जो ग्रामीण विकास के माध्यम से जितनी भी परियोजनाएं चलायी जा रही है उसके लिए एक स्टेट क्वालिटी मौनिटरिंग एजेन्ट भी है और वह हर चीज को बड़ी बारीकी से मौनिटर कर रहे हैं ताकि जहॉं पे किसी काम में लैन्प्सेज होते हैं जहॉं पे किसी काम में किसी गुणवता में कमी होती है वहॉं पर उसको सलाह दी जाती है और उसको उसीतरह से समाधान किया जाता है । क्रमशः

टर्न–17/विजय/ 01.12.16

श्री मेवालाल चौधरी: (क्रमशः) सभापति महोदय, आज के देश में आर्थिक संकट आ गयी है और वैसी आर्थिक संकट से किसान जूझ रहे हैं । इस समय बड़ा हर्ष होता है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार बिहार राज्य में भी इतने आपदा, इतने मौसम के बेरूखी के बावजूद भी 80 से 82 लाख मेट्रिक टन चावल का पैदा किया जो पिछले पांच साल में ऐसा कभी उत्पादन नहीं हुआ था । और आज के दिन में भारत सरकार में जो आर्थिक संकट पैदा हुई है शायद आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी न बन जाय । अभी रबी फसल लगायी जा रही है । अभी गेहूं, चना और मसूर लगाया जाएगा । किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे समय पर कोई चीज खरीद ले, समय पर वह हर चीज को लगाये । सभापति महोदय हर चीज रूक सकती है लेकिन किसान की किसानगिरी का समय नहीं रूक सकता है । अगर समय पर किसी की बुआई नहीं हुई, अगर समय पर किसी चीज की रोपाई नहीं हुई तो शायद हम जिस मंशा के साथ फुड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम जिस सोच के साथ सेल्फ हेल्प सेल्फ सर्पोटींग की बात कर रहे हैं शायद हम उसमें कामयाब नहीं होंगें । इसलिए इस आर्थिक संकट को शायद भाजपा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा संकट आने वाले दिनों में होगा । पता नहीं हम जी.डी.पी. की बात नहीं करेंगे अभी इसका कोई कलकुलेशन फिगर नहीं आया है लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खासकर कृषि के जी.डी.पी. में जरूर कमी आएगी ।

सभापति(श्री नरेंद्र नारायण यादव):माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का समय बचा है।

श्री मेवालाल चौधरी: सभापति महोदय, हम एक ही चीज बताना चाह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कानून में विश्वास करते हैं और यह राज्य कानून का राज्य है । बहुत सारी अवधारणा थी लोगों में वह अवधारणा अब टूट चुकी है । इसलिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना था जो न्याय न्यायपलिका है वह अनुमंडल स्तर पर होता जा रहा है ।

अंत में माननीय मंत्री जी से मेरा अपना एक समस्या है क्षेत्रीय असरगंज प्रखंड में आज पिछले 25 साल से ब्लॉक का अपना कोई बिल्डिंग नहीं बना हुआ है । मैं अपने माननीय मंत्री, आदरणीय श्रवण जी से निवेदन करेंगे कि असरगंज प्रखंड में ब्लौक का निर्माण करने के लिए सरकार तुरंत फैसला लें और जो भी पैसे का आवंटन हो उसको करें । साथ ही साथ एक ब्लौक जो टेटियामुंबन में अभी बन रहा है वहां स्थल का चुनाव किसी कारणवश गलत ढंग से हो चुका है हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस पर भी विचार करें और विचार करके जो भी जनता के हित में फैसला हो वह फैसला दें । धन्यवाद महोदय ।

सभापति(श्री नरेंद्र नारायण यादव): माननीय सदस्या, श्रीमती समता देवी ।

श्रीमती समता देवी: सभापति महोदय, मैं आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पेश किये गये अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं ।

महोदय, राज्य के 80 प्रतिशत से अधिक आबादी आधी आबादी गांवों में निवास करती है । इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रो के विकास की । महोदय, देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा । लेकिन भारत विकसित देश तभी बनेगा जब बिहार का सर्वांगीन विकास होगा । बिहार का विकास तभी हो सकता है जब इसके ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास हो । महोदय, यह सच है कि पिछले आठ नौ वर्षो से विकास की किरण हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम, जन उपायोगी योजनाएं राज्य सरकार ने लागू किया है पहले जहां कच्ची सड़क नहीं थी वहां आज पक्की सड़क है । जहां लैंड लाइन फोन नहीं था आज वहां मोबाइल सेवायें पहुंच गयी हैं । राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। गांव के लोगों को आवागमन में सहुलियत हो रही है । पथ से बच्चों को स्कूल जाने आने की सुविधा हो रही है । खासकर पक्की सड़क बन जाने से दुर्घटना में काफी कमी हो गयी है । गर्भवती महिलाओं को सुविधा के लिए आसानी से स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया जा रहा है । पथ बन जाने से गांव गांव घर घर बच्चों वाहन और एम्बुलेंस पहुंच रही है । इस तरह से गांव की पूरी तरह से विकास हो रहा है । घर घर तक पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का सरकार का सात निश्चय महागठबंधन सरकार का निश्चय है । इससे गांव की महिलाओं को काफी सुविधा हो गयी है पानी लेने के लिए इन्हें जो चापाकल पर लाइन लगाना पड़ता था उससे महिलाओं को छुटकारा मिल गया है । इससे समय की बचत होती है ।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र की विषय वस्तु से सरकार का घ्यान दिलाना चाहती हूं । सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है और वह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है । इस कारण सड़क, बिजली और अस्पताल अति आवश्यक है। इन बातों का सर्वेक्षण कराकर जल्द से जल्द कार्य कराने की कृपा प्रदार करें ।

सभापति(श्री नरेंद्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मेश्वर राय जी ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: सभापति महोदय, आज के बजट पर बोलने का अवसर दिये इसके लिए हम आभारी हैं । ग्रामीण विकास जो गांव के विकास का एक बहुत बड़ा संरचना इनके पास है । खासकर महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, देश का विकास होगा देश सुंदर होगा । उसी परिप्रेक्ष्य में आज लग रहा है कि बिहार का जो ये बजट है ग्रामीण विकास विभाग का लगता है कि गांव के विकास प्रति बहुत ही प्रतिबद्धता है । हमारे माननीय नीतीश कुमार जी जो महात्मा गांधी का जो सपना था महात्मा गांधी जो कहे थे अपने आदेश में कि गांव के विकास

से देश बेहतर होगा, गांव में शौचालय बनने से, गांव के सड़क, गांव की नली और गली बनने से गांव सुंदर होगा तो देश की प्रगति या जो भी उन्नयन है वह होगा । आज कभी बिहार का बजट हमको लगता है कि मुंबई महानगर से कम होता था लेकिन आज एक ऐसा बजट है ग्रामीण विकास का जिससे लगता है कि लगता है किसी छोटे राज्य से भी बड़ा बजट है । यह गौरव की बात है । यह विकास का प्रतीक है कि बढ़ता विकास बढ़ रहा बिहार है । यह निश्चित रूप से सराहनीय है । हम चाहेंगे कि जो गांधी जी का सपना था पूरा करने का हमारे जो विरोधी जो भाजपा के भाजपाई लोग हैं वे जो यहां विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं, ये गांव विरोधी हैं । आज सदन छोड़ दिये हैं । हमको लगता है कि भाजपा के लोग गांव विरोधी हैं । आज देखिये कि ग्रामीण विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है बजट पर तो वे छोड़ दिया हैं । यह असराहनीय और निंदनीय है । और यह पास करना चाहिए कि ये गांव विरोधी हैं । साथ ही हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो ग्रामीण विकास का बजट है उसको और समृद्ध किया जाय । हमारे नीतीश कुमार जी जो गांव के सपनों को गांव को सुंदर बनाने का जो उनका सपना है वह बहुत महत्वपूर्ण है । सात निश्चय में लगता है कि जो गली और नाली साथ ही घर घर बिजली और बिजली के साथ साथ शिक्षा या जिस रूप में उन्नयन हो रहा है आने वाले समय में हमारा बिहार देश का मॉडल बनेगा । जिस रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश में बिहार को सुंदर बनाने का जो सपना है लगता है कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में इस देश का भूगोल होगा, देश का इतिहास होगा । देश के आने वाले समय में एक मेसेज देंगे । हम चाहेंगे सरकार से कि जो ग्रामीण विकास के स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें एक बड़ी जरूरत है वह है मोनीटरींग मजबूत किया जाय । मोनीटरींग इसलिए मजबूत किया जाय मोनीटरींग इसलिए मजबूत किया जाय कि आज भी गांव में जो भी लोग हैं उनको सक्रिय बनाकर जो सरकार द्वारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है वह बढ़िया से बने । उसकी खासकर निगरानी और नियंत्रण और मजबूत किया जाय । साथ ही हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारा गांव सुंदर गांव हो जिससे हमारे गांव का विकास होगा । साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे यहां की क्षेत्र की कुछ समस्या है ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित । हमारा क्षेत्र जो है लौकहा विधान सभा वह नेपाल के सीमावर्ती पर है ।

क्रमशः

टर्न–18/01.12.2016/बिपिन

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः हमारा क्षेत्र लौकहा विधान सभा नेपाल के सीमावर्त्ती पर है । हम चाहेंगे कि वहां का जो ब्लॉक है, वहां का जो प्रखंड मुख्यालय है, वह जर्जर है । हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि खुटौना प्रखंड और लौकही प्रखंड का मुख्यालय नवनिर्मित हो जिससे सीमा के चलते वहां बहुत काम ठीक से नहीं हो पा रहा है । हम चाहेंगे कि

वहां नया भवन का निर्माण किया जाए । साथ ही, और जो भी सुविधा है सीमावर्त्ती इलाके में, अधिक-से-अधिक वहां मुहैया कराया जाए । जो दूर-देहात या नेपाल का जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्त्ती इलाका है उसमें अधिक-से-अधिक काम आवे । साथ ही, हम ग्रामीण विकास पर चाहेंगे कि कुछ और नयी योजना की जरूरत है, जैसे, जीविका है। जीविका की और प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जैसे शराबबंदी है । निश्चित रूप से उसको समाज से जोड़ा जाए । समाज की जो भी महिला वंचित है उसको जोड़ा जाए और गांव में एक नया कार्यक्रम किया जाए । सेमिनार या फिर सभा से सरकार को संकल्पित या सरकार को नया रूप देना चाहिए ताकि गांव की अधिक-से-अधिक महिला को उसमें जोड़ें । शराबबंदी, खासकर सीमावर्त्ती इलाका में आज भी लोग थोड़ा-बहुत सीमा पार से आकर चोरी-छिपे शराब पर अभी ध्यान दे रहे हैं । हम चाहेंगे कि महिला की जागरूकता पर सीमावर्त्ती इलाका में यह जो ग्रामीण विकास है, एक नया नीति लाना चाहिए, नया एक कानून बनाना चाहिए जिससे महिला की भूमिका अग्रणी हो । यदि महिला जगेगी तो निश्चित रूप से शराबबंदी पर रोक और मजबूती से लगेगी । साथ ही हम चाहेंगे कि शराबबंदी के साथ-साथ महिला जागरूकता और जो साक्षरता है, सीमावर्त्ती इलाका में कम है । हम चाहेंगे कि इसपर नया कोई नयी नीति बने, कोई विशेष रूप से नेपाल का सीमावर्त्ती इलाका है उसमें नीति बने जिससे आने वाले समय में शराबबंदी के साथ-साथ हमारी सामाजिक चेतना का भी स्तर बढ़ेगा और हमारी पुलिस और जो भी है उससे भी मुक्त हो जाएंगे । हम चाहेंगे ग्रामीण विकास मसले पर कि मोनिटरिंग के बारे में जरूर ध्यान दिया जाए । इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमको बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

श्री नवाज आलम : सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं ।

महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास से संबंधित द्वितीय अनुपूरक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, आज बहुत सारे साथियों ने बहुत ही विस्तार से, खासकर रामदेव बाबू जैसे लोगों ने और बहुत ही पुराने-पुराने साथियों ने बहुत-सी बातें रखने का काम किया। मैं एक ही बात तमाम अपने माननीय सदस्यों से कहेंगे कि हमलोग जो महागठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग -

'सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि बिहार की सूरत बदलनी चाहिए ।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,

हो कहीं आग, मगर आग जलनी चाहिए ।'

सभापति महोदय, इन्हीं संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और महागठबंधन के डिप्टी सी.एम. तेजस्वी जी, तमाम गठबंधन के लोग, सोनिया जी का, तमाम लोग का एक संकल्प है, वह संकल्प है पूरे हिन्दुस्तान में कहीं-न-कहीं बिहार जो है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे कृषक के मामले में हो, चाहे राजनीतिक मंच के मामले में हो, नम्बर अव्वल पर रहा है । उसी कड़ी में लाने का प्रयास महागठबंधन के लोगों ने जो किया है उसी कड़ी में ग्रामीण विकास का आज जो सदन में प्रस्ताव है निश्चित रूप से उस प्रस्ताव के समर्थन में हमलोग बोलने के लिए खड़े हुए हैं साथियों ।

ग्रामीण विकास जब गांव में, ठीक ही कई साथियों ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच थी कि गांव में आत्मा बसती है । गांव में विकास तमाम जन-जन में जो बसने वाले गरीब-गुरबे हैं, उनकी आत्मा गांव में बसती है । उसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन के तमाम नेताओं ने संकल्प लिया था कि बिहार की तस्वीर और सूरत को बदलेंगे । उसी कड़ी में हमलोगों ने सात निश्चय जैसे महत्वपूर्ण कदम को लेने का काम किया था और महत्वपूर्ण कदम जो है, सात निश्चय कोई छोटा-मोटा निश्चय नहीं है साथियों । सात निश्चय के माध्यम से बिहार में लोगों को, युवाओं को बताने का काम किया गया । बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना निश्चित रूप से सराहनीय कदम है साथियों । इसी तरह से तमाम युवाओं को रोजगार देने के मामले में इन्हीं संकल्प के साथ हमने कहा था । ठीक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन के साथियों ने एक संकल्प के साथ कहा था -

'यकीन है हमको कि बढ़ते जाएंगे कदम,
हमको मंजिल पर हमारा हौसला ले जाएगा ।'

इसी कड़ी में ग्रामीण मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14,27,825 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया । इसी तरह वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22 नवम्बर, 2016 तक कुल 11,96,151 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इसके लिए मैं ग्रामीण मंत्रालय को और तमाम यहां जो हमारे गठबंधन के मुखिया को इस कड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं । मनरेगा के अंतर्गत 2015-16 में 90 या अधिक दिनों तक रोजगार देने का प्रयास किया गया । इसी तरह से सभापति महोदय, वेयर फुड टेक्निशियन का भी चयन किया गया जो 308 को लाभान्वित किया गया है। फोकस एरिया के कार्यों में 2017 में कुल 24,204 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया । महोदय, सबसे बड़ी योजना शौचालय योजना जो गांव-गांव के जो हमारी मां-बहनें जो गरीब थी, वंचित थी, उन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी मां-बहनें कहीं-न-कहीं, जब रात में कहीं हमलोग चलते थे, गांव में रहने वाले लोग रात में गाड़ियों से

चलते थे तो हमारी मां-बहनें उस काम-शौच के दौरान, हमारी मां-बहनें भी महसूस करती थी । उस कड़ी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने, महागठबंधन के तमाम नायक लोगों ने फैसला किया कि हम शौच से गांव को मुक्त कराएंगे । उसी कड़ी में भोजपुर की धरती पर हमने देखा है महोदय कि स्वच्छता अभियान में मेजरी पंचायत को शौच से मुक्त कराया गया, पिरौटा पंचायत को शौच से मुक्त कराया गया । इसी तरह, उदवंतनगर प्रखंड में कुसबा पंचायत में जहां आदरणीय मंत्रीजी भी गए थे, उस पंचायत को शौच से मुक्त कराया गया । यह सराहनीय कदम है महागठबंधन के साथियों का । इसलिए इस माध्यम से जैसे महिला सशक्तिकरण का मामला है महोदय, महिला सशक्तिकरण के मामले में हमारे गठबंधन के लोगों ने जो 35 प्रतिशत् रिजर्वेशन दिया, उसी की कड़ी है कि पंचायत से लेकर सदन में तमाम सदस्य महिला साथी नजर आ रही हैं । इसी तरह महोदय, इन्दिरा आवास योजना है । इन्दिरा आवास योजना जो दिनांक 22.11.2016 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किए गए आवास की संख्या 3,10,545 है । इसी तरह से, आज हमलोग इन्दिरा आवास के मामले में उत्तर प्रदेश, पूरे हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, हमलोग दूसरे नम्बर पर हैं। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने सदन को, अपने माननीय मंत्री को आदरनीय महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी को, लालु जी, तेजस्वी जी जैसे लोगों को, सोनिया जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने जो महागठबंधन की सरकार चलाई, उसमें इ.सी.सी. डाटा वाले गांव की जनसंख्या 39519 है .....क्रमशः.

टर्न:19/कृष्ण/01.12.2016

श्री नवाज आलम (क्रमशः) लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कुल भौतिक लक्ष्य 1 करोड़ 66 लाख दिया गया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज खोले गये, भोजपुर, महुआ, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय इन तमाम जगहों पर नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं । यह एक ऐसा आयाम है, जो सचमुच में काबिले तारीफ है । इसी तरह से एम्बुलेंस में 300 की वृद्धि की गयी । सारे अस्पतालों को अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जोड़ा गया । एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कहीं न कहीं बढ़ता हुआ बिहार के साथ है । इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कोट किया था, उसी के सामने कहा था कि महागठबंधन के नेता ने उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है । नेल्सन मंडेला ने कोट किया था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल विपन, वी कैन यूज चेंज द बिहार । महोदय, उसी कड़ी को जोड़ते हुये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा जगत में जो बच्चों को साईकिल दिया, प्रोत्साहन राशि दी और छात्रवृत्ति दिया,

इसकी एक कड़ी उदाहरण है बढ़ता बिहार, जो सचमुच में विपक्ष के साथियों को नागवार गुजर रहा है । इसी तरह से हमलोग आगे की कड़ी में कई ऐसी योजनाओं को लेने का काम किया है । महोदय, इसीलिये ये लोग घबराये हुये हैं। महोदय, महागठबंधान के नाम पर एक शेर कहना चाहता हूं कि

मैं अमन पंसद हूं,
मैं अमन पसंद हूं,
मेरे शहर में दंगा रहने दो,
मैं अमन पंसद हूं,
मेरे शहर में दंगा रहने दो,
लाल हरे में मत बांटो,
मेरे छत पर तिरंगा रहने दो ।

इसी कड़ी के साथ साथियों सचमुच में बिहार की बढ़ती हुई तस्वीर को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने, तेजस्वी जी ने, सोनिया जी ने जो संकल्प लिया था, उसको धरातल पर लाने का काम किया है । हमारा एक मकसद था कि गरीब-गुरबे की आवाज सदन तक पहुंचे । हमारा एक मकसद था कि हमारे गरीब-गुरबे की आर्थिक स्थिति मजबूत हो । हमारा शौचालय हो, उस कड़ी में जो आदरणीय नेता ने, महागठबंधन के नेताओं ने जो काम किया है, वह सराहनीय है । इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं पुनः ऐसे नेताओं का इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं । इसी कड़ी में महागठबंधन के साथी लोग तेजस्वी जी को एक होनहार और एक काबिल नेता के रूप में देखना चाहते हैं । उनके ऊपर हम एक शेर अर्ज करना चाहते हैं -

वे खुद ही जान जाते हैं,
वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की,
परिन्दों को नहीं तालिम दी जाती उड़ानों की ।

महोदय, उन्होंने पथ निर्माण विभाग में जो उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिये महोदय, कोई बनावटी बात नहीं है, कच्ची दरगाह से विदुपुर 6 लेन ब्रीज का कार्यक्रम, आरा एन0एच0, छपरा एन0एच0, भाया भकुरा डोरी गंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण, भागलपुर का सुल्तानगंज एवं खगड़िया के बिहपुर में निर्माण, फ्लाई ओवर का निर्माण, पटना शहर को ट्रैफिक मुक्त करने का काम, सभापति महोदय, यातायात के जाम से लोग तबाह रहते थे, उससे मुक्त कराने का काम किया गया है । .. पी.एम.यू. की व्यवस्था की गयी, जो दुर्घटना हो जाती थी, उस दुर्घटना से निजात दिलाने के लिये उन्होंने एक नये कदम उठाने का काम किया है । मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना 246 पूर्ण किया गया है । तमाम उपलब्धियों में चाहे आप नगर विकास विभाग के मामले में उठाये, नगर विकास विभाग में पटना ने अभूतपूर्व काम किया है, पटना मास्टर

प्लान को 2031 मैप रिपोर्ट है, स्वीकृत किया गया है । महोदय, 70 पार्कों का जिर्णोद्धार किया गया है । गुरू गोविंद सिंह महाराज का जन्म दिन, जो आज प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसमें पचीसो पथों का जिर्णोद्धार किया गया है । 6 फुट ओवर ब्रीज का काम अभी प्रगति पर है । इस तरह से महागठबंधन के लोगों ने लगातार तमाम चीजों पर चाहे वह ग्रामीण विकास मंत्रालय का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जनहित का मामला हो, तमाम मामलों में अपना एक अहम भूमिका अदा करने का काम किया है । इसलिए सदन के माध्यम से अपने महागठबंधन के तमाम नेताओं का अपने तमाम जनप्रतिनिधियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुये अपने वाणी को विराम देता हूं । जय हिंद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री राजेंद्र कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज ग्रामीण विकास विभाग के द्वितीय अनुपूरक मांग के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महोदय, आज महागठबंधन के द्वारा जो सूबे बिहार में विकास का काम किया जा रहा है, आज ग्रामीण विकास के माध्यम से गांव में बसनेवाले गरीबों का जो हालत खराब था, जो स्थिति खराब थी, महागठबंधन की सरकार ने गरीबों के प्रति सोचने का काम किया है और जिसका प्रतिफल है कि गांवों में संपर्क पथ नहीं था, गांवों के गरीबों को कभी नसीब नहीं था, पगडंडी पकड़ कर गांव के लोग अपने घरों में जाते थे, लेकिन ग्रामीण विकास के माध्यम से जहां गरीबों को सिर छिपाने के लिये इन्दिरा आवास के माध्यम से छत देने का काम किया जाता है, वहीं पर गांवों में संपर्क पथ के अभाव में लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी । हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम आभार प्रकट करना चााहेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी को कि आपने महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुआई में, डिप्टी सी0एम0 जो पूरे देश के नौजवानों के दिलों की धड़कन हैं, भाई तेजस्वी जी के प्रयास से आज पूरे बिहार में जो काम हो रहे है, वह काबिले तारीफ है । हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, वहां महागठबंधन जो काम कर रही है, वह देख कर बीजेपी वालों के दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है, पूरे देश में आज माहौल बना हुआ है, बिहार के विकास को देख कर उसका अनुकरण किया जा रहा है, हम कहना चाहेंगे, सूबे बिहार के मुख्यमंत्री के प्रयास को आज गांवों में जो शौचालय बन रहे हैं, आज गरीबों के बीच जो हालात बने थे, गरीब महिलायें लज्जा की शिकार होती थीं, अपने घरों से निकलकर दूसरे के खेतों में शौंच करने जाती थी, वह प्रताड़ित हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो प्रयास किया गया है, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो शौचालय का निर्माण करा कर के गरीबों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है, इसके लिये हम महागठबंधन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बिहार की जनता आज

दिन-रात महागठबंधन का गुणगान कर रही है, आज नोटबंदी के माध्यम से बिहार में जो हालात गरीबों के बीच पैदा किया गया है, आज गरीबों को शब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया हैं । आज किसान अपने खेतों में सही रूप से खाद का उपयोग पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं । भाजपा के लोग देश को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं । देश के साथ, गरीबों के साथ बेईमानी करना चाहते हैं, बिहार की सरकार महागठबंधन के माध्यम से देश के गरीबों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसी हालत में आज नोटबंदी के माध्यम से, बिना व्यवस्था का, बिना प्लान का, देश में जो नोटबंदी लाया गया, गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है । आज बिहार को 50 साल पीछे भाजपा के लोगों ने भेजने का काम किया है । गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है । देश की जनता कभी भी इन्हें माफ करनेवाली नहीं है । हम कहना चाहेंगे कि आज देश में महागठबंधन के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से जो शौचालय का निर्माण हो रहा है, गांवों में हर जगह शौचालय का निर्माण तरीके से करने की जरूरत है । आज मनरेगा के माध्यम से काम करने का जो प्रयास, 100 दिनों का रोजगार बिहार सरकार के द्वारा मुह्हैया किया गया है, 100 दिन जो रोजगार दिया गया, उसमें पिछले दिनों जो मजदूर काम किये थे, आज गांवों में विधान सभा के सदस्य जाते हैं, हमारे माननीय सदस्य जब गांव में जाते हैं, जो हालात बना हुआ है, बिहार सरकार जो पूर्व में काम करवाई, यह भारत सरकार के बेईमानी की वजह से गरीबों को जो रोजगार सेवक के द्वारा मैनडेट भेजा गया और भारत सरकार के द्वारा गरीबों को जिन्होंने मनरेगा में काम किया, उन कार्यों का अभी भी, उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से गरीब आज भी आस लगाये हुये हैं ।

क्रमश :

टर्न-20/राजेश/01.12.16

श्री राजेंद्र कुमार, क्रमशः- हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसतरह से इंदिरा आवास में कटौती किया गया है, तो इंदिरा आवास में कटौती का मतलब है कि देश के गरीबों के सर से छत का छीनना, तो हम जानना चाहेंगे इस देश में विकास का ढ़िढोरा यह नरेन्द्र मोदी की सरकार, यह भाजपा की सरकार पिटती है लेकिन गरीबों के मनरेगा में कटौती और इस देश में इंदिरा आवास में कटौती करके गरीबों के बीच आखिर मैसेज क्या देना चाहती है ? हम तो कहना चाहेंगे बिहार की सरकार को, महागठबंधन सरकार को कि बिहार की जनता धन्यवाद देना चाहती है, इतिहास में इतने अच्छे तरीके से बिजली उपलब्ध बिहार की धरती पर कभी नहीं किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा बिजली के संबंध में जो कार्य किये गये हैं, वह काबिले-तारीफ है । हम कहना चाहेंगे इस देश

में भाजपा वाले हमेशा, जब इस देश के गरीबों के संबंध में कोई मुद्दा आता है, तो सदन से ये वाकआउट करने का काम करते हैं, सदन को बाधित करने का काम करते हैं, आज भाजपा वाले इस सदन में नहीं है सभापति महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज देश गवाह है और आज यह सदन गवाह बनेगी कि आज बिहार जो विकास के रास्ते पर जा रहा है, गरीबों के लिए जो काम कर रही है महागठबंधन की सरकार, तो महागठबंधन की सरकार जब गरीबों के लिए काम कर रही है, तो जब-जब कोई विकास की बातें गरीबों के हित में होता है, तो ये भाजपा वाले विधान सभा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, विधान सभा को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर यह बिहार की जनता को लुभावना मंत्र दे करके, गरीबों का वोट लेने का जो काम किये हैं, अब भाजपा वाले को बिहार की जनता पहचान गयी है और आज बिहार की जनता देखना चाहती है कि अगर ये लोग आज उनके पास वोट माँगने के लिए चले जायें, तो बिहार की गरीब जनता इन्हें सबक सिखने का काम करेगी । आज हम यह बतलाना चाहेंगे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कि जो आज विकास का काम हो रहा है, उससे निश्चित तौर पर आज बिहार में खुशी का माहौल है, हर जगह खुशी का माहौल है, महागठबंधन सरकार की तारीफ हो रही है, तो यह देख करके भाजपा वाले के पेट में दर्द शुरु है । हम निश्चित तौर पर यह कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के माध्यम से आज गरीबों के घर में शादी रुक गयी है, किसानों के खेत में फसल नहीं लगे हैं और इसका असर निश्चित तौर पर केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हालात ये पैदा करना चाहते हैं, वह गरीबों के हित में नहीं बल्कि यह गरीबों के अहित में है और इसके बदले बिहार की जनता और देश की जनता इनको सबक सिखलाने का काम करेगी । उसीतरह से हम आरक्षण के बारे में कहना चाहते हैं महिला के विषय में । ये भाजपा वाले सदन में हल्ला मचाते हैं कि महिला को अपमानित किया जाता है लेकिन बिहार में यह इतिहास बना है कि महागठबंधन की सरकार महिलाओं को जो मान-सम्मान दे दिया, तो देश के इतिहास में आज तक इतना मान-सम्मान महिलाओं को महागठबंधन की सरकार ने जितना दिया, वह आज तक किसी दूसरे दल ने नहीं देने का काम किया है । सभापति महोदय, आज जीविका के माध्यम से जो महिलाओं को मान-सम्मान दिया गया है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को जीविका के माध्यम से कि आज गाँव-गाँव में इस सरकार के द्वारा जो लाभकारी योजनाएँ चलायी जा रही हैं, उन तमाम योजनाओं को गरीबों और सरजमीं तक उतारने का काम यह जीविका द्वारा स्वयंसेवी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को । सभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे, इतिहास गवाह है, हम जिस जाति से आते हैं, अनुसूचित-जाति के आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, यह सरकार जब आरक्षण

नहीं दी होती तो निश्चित तौर पर महात्मा गॉधी जी के सपनों को साकार करने में जो एक ताकत मिली है, आज गॉव-गॉव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित-जनजाति, अति पिछड़ा और गरीब समाज के लोग, आज पंचायत में जो प्रतिनिधि बने हैं, वे आज निश्चित तौर पर सम्मानित हुए हैं, आज वे आर्थिक रुप से, सामाजिक रुप से जो मजबूत हुए हैं वह महागठबंधन का देन है और हम कहना चाहेंगे और यह देश गवाह है, निश्चित तौर पर गॉव-गॉव में हम मानसिक रुप से मजबूत हुए, यह हम कहना चाहेंगे । हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जो सामाजिक रुप से गरीब लोगों को मजबूत किया गया और आज की कड़ी में माननीय उप-मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामाजिक रुप से, आर्थिक रुप से, उसी कड़ी में आज काम करके देश और दुनिया में इन गरीबों को मजबूत करने और खास करके इस बिहार में गरीबों को मजबूत करने का जो काम आरक्षण के माध्यम से किया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने समाज की तरफ से महागठबंधन की सरकार को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आप दिन-रात गरीबों के हित की बात करते हैं, गरीबों के बारे में सोच रखते हैं और विदेशों में जा करके आज भारत की सरकार के द्वारा मॉर्डन सिटी और स्मार्ट सिटी की बात होती है लेकिन आज 80 प्रतिशत गॉवों में रहने वाले लोग, आज देश की जो हालत है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा गॉवों का देश है और गॉवों का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है लेकिन ये भारत की सरकार विकास की बात तो करती है, यह स्मार्ट सिटी की बात करती है, पटना शहर को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो जब भारत की सरकार पूरी ताकत से विकास की बात करती है, तो इस देश में सबसे ज्यादा आहत गॉवों में बसने वाले लोगों को होता है और विकास की हर धारा गॉवों के विकास से ही खुलता है और आज जो रोजगार की हालत है, रोजगार में यह सरकार, हमारी महागठबंधन की सरकार, 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था की और आज जो 100 दिनों का रोजगार गरीबों को मुहैया हो रहा है, तो भाजपा के लोगों को इससे घबराहट हो रही है, तो इसमें भारत सरकार ने रोजगार और काम-काज के सिस्टम में कटौती करने का काम जो किया गया है, तो हम कहना चाहेंगे कि देश की जनता और बिहार की खास करके गरीब जनता को भाजपा जिस नियत से बिहार की जनता को तबाह करना चाहती है, तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता उनको सबक सिखने का काम करेगी । सभापति महोदय, हम कहना चाहेंगे कि आज जो हालात देश का है, आज ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से हर गॉव में संपर्क पथ का व्यवस्था किया जा रहा है, आज हर गॉवों में नली और गली का व्यवस्था किया जा रहा है और पहले नली और गली के अभाव में हम जब गरीब मजदूरों के बीच जाते हैं और गरीब मजदूरों का जो हालत होता है नाली के अभाव में और गली के अभाव में, वे

इससे पहले जानवर की स्थिति में जीते थे लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को कि गॉवों में बसे हुए गरीबों के प्रति जो सोच महागठबंधन की सरकार का है लेकिन आज के दिन भाजपा वाले हल्ला करते हैं कि नोटबंदी के खिलाफ यह सरकार है, हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं बल्कि यह आपकी व्यवस्था के खिलाफ यह महागठबंधन की सरकार पहले भी आवाज उठाते रही है और आज भी आवाज उठा रही है कि जो व्यवस्था है, वह निश्चित तौर पर गरीबों के हित में नहीं है बल्कि यह गरीबों के अहित में है । इसलिए हम कहना चाहेंगे और आज हम हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कि आज जो गॉवों में हालात है, वह निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो प्रयास है, वह प्रयास सराहनीय है । हम कहना चाहेंगे कि गॉवों में आज जो शौचालय बन रहे हैं और उस शौचालय की जो स्थिति है, उसमें जो 12 हजार रुपया तय हुआ है केन्द्र सरकार के माध्यम से कि शौचालय बनाने के बाद वह 12 हजार रुपया दिया जायेगा, तो आज गॉव के गरीब दो-दो रुपया के लिए विवश हो जाते हैं, आज हालात उनकी यह हो गयी है कि अगर यह बात पहले से होती तो अपने से वे शौचालय का निर्माण करा लेते, इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि यह जो हालात है शौचालय बनवाने का या भारत सरकार के द्वारा जीविका के माध्यम से अन्य प्रकार से इसे परिचारित करके, इसे हर तरह से जमीन पर उतारने का जो प्रयास हो रहा है, तो इसमें 12 हजार रुपये की जो बात है, यह राशि पहले गरीबों के खाते में चला जाय, यह हम सदन के माध्यम से मांग करेंगे ताकि वह उसा पैसा को लगा करके हर घर में निश्चित तौर पर शौचालय का निर्माण हो सके और पहले जिन गरीबों के घर में स्वच्छ जल नसीब नहीं होता था, तो बिहार सरकार ने इसमें फैसला लिया है कि हम 7 निश्चय के माध्यम से जो यह फैसला आया है कि गरीबों के गॉव में और गॉव-गॉव में हर जगह नल का जल का व्यवस्था कराया जाय, यह काबिले-तारीफ है । आज गरीब के घरों में जब बिमारी होती थी, तो इसका दूसरा कोई कारण नहीं था, इसका सबसे बड़ा कारण था स्वच्छ जल का अभाव उनके घरों में होता था, वह कहीं से अपनी गाढ़ी कमाई को ला करके किसीतरह भोजन तो कर लेते थे लेकिन उनको स्वच्छ जल का अभाव होता था, इसके चलते उनके घरों में अनेक प्रकार की बिमारियॉ होती थीं, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार को कि 7 निश्चय के माध्यम से कि गरीबों के लिए जो स्वच्छ जल की व्यवस्था की गयी है, यह निश्चित तौर पर उनके सेहत को और उनके विकास को मद्देनजर में रखकर किया गया है । हम भारत सरकार को कहना चाहेंगे कि इस देश में शैक्षणिक रुप से जो मजबूत हो रही थी बिहार की गरीब जनता और उसमें खास करके बिहार की अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति और अति पिछड़ा के गरीब लोग जब मजबूत होने लगे शैक्षणिक रुप से, तो यह निश्चित तौर पर भारत की सरकार जो है,

भाजपा की सरकार की धड़कन बढ़ी और हम कहना चाहेंगे और इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को कि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या दो हजार रुपये प्रतिमाह ग्रैजुएट के छात्रों को दे करके प्रतियोगी परीक्षा में बाहर के प्रोविंसो में भेजने का जो प्रावधान लाया गया है, इसके लिए भी हम महागठबंधन की सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे ।

क्रमशः

टर्न-21/सत्येन्द्र/1-12-16

श्री राजेंद्र कुमार (क्रमशः) गांव के गरीब जब किसी तरह से मैट्रिक पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है और स्नातक करने के बाद उनके अभिभावकों को प्रतियोगी परीक्षा में भेजने के लिए पैसे नहीं हुआ करता था जिससे बहुत सारे प्रतियोगी प्रतिभावान बच्चे बाहर जाकर के परीक्षा दे नहीं पाते थे और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे । हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को कि आज गरीब के बच्चों का ख्याल करते हुए गरीबों को शैक्षणिक क्षेत्र में मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गरीबों को 2000 रू0 दो साल तक देने का जो फैसला आया है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गरीब के बच्चे जाकर के शामिल हों और प्रतियोगी परीक्षा में पासकर के वह देश के बिहार के किसी भी कोने में किसी दफ्तर में काम कर सके, वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सके इसके लिए भी हम महागठबंधन सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसलिए कि निश्चित तौर पर जब बी0ए0 पास हो जाने के बाद वह कम्पीटेटिव स्तर पर मजबूत होना चाहते थे, प्रतियोगिता एक्जाम देकर बड़े ओहदा पर जाना चाहते थे, वह पैसा के अभाव में नहीं जा पाते थे लेकिन आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर देश ही नहीं दुनिया इसकी तारीफ कर रही है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गरीब के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सरकार की पहल और उद्देश्य है इसके लिए भी महागठबंधन सरकार काबिले तारीफ है । हम कहना चाहेंगे कि इससे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घरों में उनके गांवों में खुशी की लहर है। हम कहना चाहेंगे कि आज सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से उन्हें मजबूत करने का प्रयास किया गया है । हम कहना चाहेंगे, ग्रामीण विकास के द्वारा जो अनेक प्रकार की योजनाएं चलायी जा रही है उसमें हम आग्रह करेंगे कि स्थानीय स्तर पर कोई अगर परेशानी होती है तो उसमें निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारी पर शिकंजा कसने का काम किया जाय और गति देने का प्रयास करें । हम कहना चाहेंगे, स्वच्छता के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जीविका के माध्यम से आज गांव में जाने के बाद दिखता है कि गांव की महिलाएं आज गांव से निकल कर के अपने तमाम दक्षता का परिचय देती है । आज गांव में सरकार के द्वारा जो लाभकारी योजनाएं चल रही है उन तमाम लाभकारी

योजनाओं को एक-एक कर के गांव में जाकर बतलाने का काम कर रही है । हम धन्यवाद देना चाहेंगे शराबबंदी के माध्यम से गांव में बसे हुए गरीबों की जो हालत जर्जर

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

था वह शैक्षणिक रूप से कमजोर थे, वह अपने दायित्व को नहीं पहचान पाते थे, वह अपने कर्त्तव्य को नहीं पहचान पाते थे, आज शराबबंदी के कारण गांव के गरीब अपने तमाम दायित्व को समझने लगे हैं, अपने कर्त्तव्य को समझने लगे हैं । आज गांव में हरेक जगह ये भाजपा के लोग शराब बांट कर के वोट लिया करते थे ये भाजपा वाले शराब वितरण कर के गांव में गरीब को लुभाने का काम और वोट लेने का काम करते थे । हम सराहना करना चाहेंगे, हम तारीफ करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि आप लोगों का फैसला और खासकर महागठबंधन के माननीय लालू प्रसाद यादव, सोनिया जी और नीतीश जी का कि आपने जो गरीबों के हित में यह शराबबंदी लाया है इससे आज गांव के गरीब जितने खुश हैं और उसके खिलाफ हम नारा लगाते थे, गांव के गरीब तैयार थे कि शराब के खिलाफ, भाजपा वाले अगर आवाज उठायेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य,अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार : इसलिए हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे कि ग्रामीण विकास के माध्यम से जो विकास हो रहा है उसकी देश और दुनिया तारीफ कर रही है इस बिहार का और निश्चित तौर पर आज जो हालत पैदा हुआ है उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि यहां विकास की गति बढ़ी है और बढ़ती रहेगी । हम अंत में एक आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि हम हरसिद्धि विधान-सभा से आते हैं, वहां पर हरसिद्धि प्रखंड के भवन की स्थिति काफी जर्जर है । प्रखंड कार्यालय का भवन नहीं है जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि उसको बनवाकर उस प्रखंड को सुचारू रूप से संचालित कराया जाय । इन्हीं बातों के साथ हम अपने शब्द को विराम देते हैं । जय हिन्द,जय भारत ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 13 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं । जिन माननीय सदस्यों ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की सराहना की है और सराहना करते हुए बहुमूल्य सुझाव दिये हैं महोदय,निश्चित रूप से उन सुझावों को ग्रामीण विकास विभाग अमल में लायेगी और उनके सुझाव को प्राथमिकता देगी । महोदय,यहां पर विपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं हैं। कटौती प्रस्ताव तो उन्होंने लिखित में पेश कर दिया महोदय लेकिन जब दूसरी पाली की बैठक शुरू हुई तो आज विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं है । महोदय, आपने दो बजे

तक सदन की कार्यवाही स्थगित की थी और फिर दो बजे से शुरू करने का आपने ऐलान किया था इसलिए दो बजे से इनको रहना चाहिए लेकिन पता नहीं इनके मन में क्या इच्छा है महोदय, बात समझ में नहीं आती है । सरकार इनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है, सरकार के सामने जो ये प्रश्न लाते हैं सरकार उसका हल निकालना चाहती है लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठी है महोदय, तब से इनका नजरिया बदल गया है और खासकर के ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब इस सदन में उस पर चर्चा हो रही है महोदय तो उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए । बिहार गांव का प्रदेश है, गांव में काफी आबादी हमारी बसती है लेकिन जब से दिल्ली में सरकार इनकी बनी है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं महोदय, तब से लगातार गरीबों के ऊपर हमला हो रहा है, गरीबों पर कहर ढाया जा रहा है जैसे हमारे इन्दिरा आवास की योजना है नाम उन्होंने बदल दिया महोदय, आवास ग्रामीण कर दिया । महोदय, आवास ग्रामीण कर देते, नाम अपना रख लेते हमको कोई एतराज नहीं होता महोदय लेकिन जब राज्य को अंश ज्यादा लगाना पड़ रहा है और केन्द्र सरकार अपने केन्द्रांश में कटौती लगातार करते जा रही है इससे स्पष्ट होता है कि गरीबों के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है, महोदय ये लोग सिर्फ गरीबों के लिए आंसू बहाते हैं । अगर गरीबों के लिए दिल में इनकी जगह रहती तो उनकी पार्टी के लोग आज यहां पर रहते और सरकार जो काम कर रही है उसमें सुझाव देते कि गरीबों के लिए ये योजना चालू किया जाना चाहिए और बहस में इनको हिस्सा लेना चाहिए । महोदय,ये बहस में नहीं आना चाहते हैं सिर्फ अखबार और टेलीविजन के जरिये बिहार की जनता को बतलाना चाहते हैं, देश की जनता को बतलाना चाहते हैं कि हम राज्य के सवालों के लिए राज्य के जनता के हित के लिए हम चिन्तित हैं लेकिन ये देश की जनता और राज्य की जनता के लिए चिन्तित नहीं है सिर्फ और सिर्फ अखबार और टेलीविजन के माध्यम से सिर्फ ये खबर फैलाना चाहते हैं महोदय। महोदय, इसी प्रकार से केन्द्र प्रायोजित जितनी योजनाएं इस राज्य में चल रही है, उन सभी योजनाओं में कटौती हो रही है । पहले राज्य को 25 प्रतिशत लगाना पड़ता था इन्दिरा आवास योजना में, अब 40 प्रतिशत लगाना पड़ेगा राज्य को, मनरेगा योजना में पहले लगाना पड़ता था 25 प्रतिशत उसमें भी अब 40 प्रतिशत लगाना पड़ेगा, इसी प्रकार जीविका की योजनाओं में भी हमें 40 प्रतिशत लगाना पड़ेगा । राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जितनी हैं, लगभग 60-67 योजनाएं यहां चल रही है उन सभी योजनाओं में इसी प्रकार से कटौती कर के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को तहस नहस करने की इनकी योजना है महोदय। हमारी सरकार हमारे महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं गांव को शक्ति देना,वे गांव की तरक्की चाहते हैं गांव का विकास चाहते हैं । यहां महागठबंधन की जब से सरकार आयी है तब से 7 निश्चय का जब नाम उन लोगों ने सुना है भाजपा के लोगों में तो इनके पेट से

लेकर शरीर तक में दर्द हो जाता है इसलिए कि गांव जब स्मार्ट बनेगा, ये तो शहर को स्मार्ट बनाने वाले लोग हैं, ये तो शहर का शहरीकरण चाहते हैं, गांव के गरीब और गांव की गलियों से इनको नफरत है, इनको प्यार है शहरों से महोदय इसलिए जब 7 निश्चय लागू होगा, उसमें एक हमारी योजना जो है ग्रामीण विकास की महोदय उसमें एक हमारी योजना है स्वच्छता का, महोदय ये हमारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान हमारी योजना है महोदय, इस योजना के जरिये हम राज्य के जो गरीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 60 लाख है जिनके घरों में शौचालय नहीं है । (क्रमशः)

टर्न–22/मधुप/01.12.2016

...क्रमशः ...

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उनके शौचालय निर्माण की हमारी योजना है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, महागठबंधन के नेताओं ने फैसला लिया है कि यह जो शौचालय लोहिया स्वच्छता अभियान चलेगा इसमें पूरी तरह से गॉव को हम स्वच्छ बनायेंगे और गॉव में जो भी लोग रहते हैं उनके घरों में शौचालय निर्माण करके बाहरी शौच से हम मुक्त करने का काम करेंगे ।

महोदय, 2019 तक हमको बाहरी शौच से, खुले शौच से बिहार को मुक्त करना है । इसी क्रम में 2017 मार्च तक खुले शौच से मुक्त करना है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1999 ग्राम पंचायत में लगभग 5299 करोड़ की लागत से 41,26,746 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य है । हमने बाहरी शौच से मुक्त बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता विधि से ग्रामीणों को खुले शौच के प्रति सामूहिक व्यवहार परिवर्त्तन करने पर भी जोर दिया है । महोदय, यह जो काम है स्वच्छता का, यह सिर्फ और सिर्फ शौचालय के निर्माण से सम्भव नहीं है, बाहरी शौच से हम मुक्त नहीं कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिये अनेक प्रकार की ऐक्टिविटी चलाई जा रही हैं । हमने पत्र भी लिखा है सभी माननीय विधायक जी को, माननीय विधान परिषद के सदस्यों को, माननीय सभी जिला परिषद के सदस्य को, पंचायत समिति और सभी मुखिया जी से भी हमलोगों ने आग्रह किया है कि इस बड़े काम में आपका सहयोग चाहिये, समर्थन चाहिये तब जाकर यह हमारा स्वच्छता अभियान सफल होगा ।

महोदय, हमने हरेक 500 प्रति परिवार ग्राम पंचायत 20 लाख रूपये का प्रावधान किया है कचड़ा प्रबंधन के लिये । इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान और वृद्ध व्यक्तियों के लिये उनका सुविधायुक्त शौचालय निर्माण करने का भी हमने फैसला लिया है । राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार के निर्देशन में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत

राज्य के वैसे लोगों का भी शौचालय निर्माण करायेंगे जो गॉव में जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं जो ए0पी0एल0 परिवार में हैं, बी0पी0एल0 परिवार से अलग हैं, उनके भी शौचालय निर्माण का काम हम करायेंगे ।

महोदय, यह सदन को बताते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत हमने एक अनुमंडल और पॉच प्रखंड को बाहरी खुले शौच से मुक्त किया है । ये प्रखंड हैं - रोहतास जिला का संझौली प्रखंड, पश्चिमी चम्पारण जिला का पिपरासी प्रखंड, सीतामढ़ी का बेलसंड प्रखंड, सीतामढ़ी का परसौनी प्रखंड, सीतामढ़ी का नानपुर प्रखंड और सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अनुमंडल खुले शौच से मुक्त हो चुके हैं ।

महोदय, इस प्रकार से हम स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं । इसी प्रकार से जो हमारा नमामि गंगा योजना है, गंगा किनारे अवस्थित हमारे जो 12 जिले हैं उनको भी 2016 तक खुले शौच से मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है - बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुॅगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली के 61 प्रखंडों के 160 ग्राम पंचायतों को हमें खुले शौच से मुक्त करना है ।

महोदय, इसी प्रकार से हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है, जीविका की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है और स्वयं सहायता समूह जो हम गॉव-गॉव में बना रहे हैं उसके जरिये ग्रामीण जो हमारी महिलाएँ हैं, ग्रामीण दीदियॉ हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने और गरीबी रेखा से उपर उठाने का काम हमारी यह जीविका कर रही है । हमने लगभग 5 लाख 65 हजार स्वयं सहायता समूह अभी तक गठन किया है और 32,421 ग्राम संगठन एवं 365 संकुल समूहों का गठन किया जा चुका है जिससे लगभग 71 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं । वित्तीय वर्ष 2016-17 में अबतक लगभग 92 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है । 2018-19 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करना है और लगभग 1.5 करोड़ परिवार को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाने का हमारा लक्ष्य है । महोदय, इसी प्रकार से 3 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक से जोड़ा गया है । इसी प्रकार से राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति के समूहों के वित्त पोषण में सुधार करते हुये ऋण की राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रूपये क रने की घोषणा की गई है । इस योजना के तहत अब तक 7,05,210 परिवारों की बीमा भी की गई है ।

महोदय, जो परिवार ताड़ी रोजगार पर आधारित परिवार थे, ताड़ी रोजगार पर आधारित परिवारों के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में नीरा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । साथ-ही, उन परिवारों को स्वयं सहायता संगठन से भी

जोड़ने का काम किया रहा है । उन परिवारों के जीविकोपार्जन के अन्य संसाधनों जैसे-डेयरी उद्योग आदि से जोड़ने हेतु जीविका को निर्देशित किया गया है ।

महोदय, इसी प्रकार जीविका-2 राज्य सरकार द्वारा राज्य के 300 प्रखंडों में गरीबी निवारण हेतु बिहार ट्रांसपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका-2 10 अगस्त, 2016 से प्रारंभ किया गया हैं । यह परियोजना विश्व बैंक सम्पोषित है, जिसके अर्न्तगत वित्तीय भार का 70 प्रतिशत भाग विश्व बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा सम्पोषित किया जाना है एवं 30 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है । इस प्रकार कुल 425 करोड़ रूपये का व्यय होगा ।

महोदय, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इस राज्य में 4,76,715 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । अभ्यर्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक-जातिगत आधारित जनगणना में आवास के लिये चिन्हित किये गये हैं, परिवारों की सूची से चयन किया जाना है । राज्य के 27 समान जिलों में 1 लाख 20 हजार उनको आवास बनाने के लिये दिया जायेगा । राज्य के 11 आई0ए0पी0 जिलों में 1 लाख 30 हजार का अनुदान देने का प्रावधान है । साथ-ही, लाभुक चाहें तो 70 हजार रूपया उनको बैंक से ऋण भी दिया जा सकता है । जो मजदूर हैं, जो जॉब कार्डधारी हैं, अगर उनको इस आवास की सुविधा मिलती है तो उनको 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी भी मनरेगा योजना के तहत दी जायेगी । इसी तरह आवास हेतु निर्धारित 20 वर्गमीटर क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्गमीटर कर दिया दिया गया है एवं शौचालय तथा रसोई घर का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है । राज्य सरकार चाहती है कि गरीबों का उत्थान आवास योजना में लाभुकों को बिचौलिया से बचाने की योजना में कार्यान्वयन में पारदर्शिता हेतु लाभुकों को सहायता राशि का भुगतान इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उनके खाते में किया जाता है । पूर्व के वर्षों में लाभुकों को देय द्वितीय किश्त की सहायता राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 310 करोड़ 14 लाख 41 हजार रूपया व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में अबतक 3,10,543 आवास पूर्ण कराया गया है । इसी प्रकार जो आवास पूर्ण कराने में दिक्कत पहुँच रहा है, जो दिक्कत हो रही है और आवास पूर्ण नहीं कर रहे हैं । महोदय, जिनको सफेद नोटिस जारी किया गया है, उनकी संख्या 4,13,674 है । जिनको लाल नोटिस जारी किया गया है, उनकी संख्या 1,76,923 है । दायर नीलाम-पत्र वाद की संख्या 11,343 है, दर्ज प्राथमिकी 131 है और वसूल की गई राशि 13,76,500 है । लगातार आवास पूर्ण कराने के लिये विभाग तत्पर है और लगातार इस दिशा में विभाग का कार्य चल रहा है ।

...क्रमशः ...

टर्न–23/आजाद/01.12.2016

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : (क्रमशः) मनरेगा योजना के तहत, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरी करने वाले इच्छुक प्रत्येक परिवार को अधिकतम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । राज्य में कुल जौब कार्डधारियों की संख्या 1,33,91,860 है, जिसमें से सक्रिय जौब कार्डधारियों की संख्या 36,36,427 है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 14 करोड़ 25 लाख है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल 11,96,151 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा अकुशल मजदूरी अन्तर्गत 3,58,4,221 मानव दिवस सृजित करते हुए 1388 करोड़ 95 लाख 14 हजार रू0 व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक 3596 परिवारों को 100 दिन काम उपलब्ध कराया गया है । महोदय, माध्यमिक उत्तीर्ण 960 सक्रिय जौब कार्डधारी जो हमारे गांव में मनरेगा में काम करते थे, कार्डधारियों को वियरफुट तकनिसियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है । प्रत्येक प्रमंडल के संबंधित जिलों के अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रमंडल के मुख्यालय जिला में कराया जायेगा । 6 प्रमंडल के 180 वियरफुट तकनिसियन का प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । प्रशिक्षण के उपरान्त वियरफुट तकनिसियन में मनरेगा अन्तर्गत कार्यों की नापी में इन्हीं को लगाया जायेगा । इसके फलस्वरूप मनरेगा के कार्यों में सुधार के साथ मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय पर करने में सहायता मिलेगी महोदय । चूँकि जब वह उसी परिवार से आयेगा तो निश्चित रूप से अपने परिवार की चिन्ता करेगा और सही दिशा में इस काम को आगे बढ़ायेगा । बढ़ते हुए प्रदूषण एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से गांव–गांव एवं पंचायत–पंचायत में वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है । इस अभियान को चलाने के लिए ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर पर निदेशित किया गया है । साथ ही साथ हर जिले में एक–एक फैसीलिटेटर बहाल किये गये हैं, जो बेहतर काम कर सकेगा, जिनकी रूचि इस अभियान में ज्यादा सक्रिय दिखेगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा । एक यूनिट में 200 पेड़ लगाये जाते हैं एवं उनकी देख–रेख हेतु दो वनपोषक बहाल किये जाते हैं, जिन्हें 100–100 दिनों का मजदूरी दी जाती है । मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना पर विशेष तौर पर अपने–अपने क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाये और महत्वपूर्ण सहयोग करें । सामाजिक वानिकी योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक सड़क किनारे 9700 इकाई, नहर एवं नदी तटबंध पर 2828 इकाई एवं निजी भूमि पर 7459 इकाई वृक्षारोपण किया गया है । मनरेगा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के

अभिसरण से लाभार्थियों के आवास निर्माण के क्रम में 90 मानव दिवस एवं नक्सल प्रभावित जिलों में 95 मानव दिवस के बराबर वित्तीय सहायता मनरेगा मद से उपलब्ध कराया जा रहा है । मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु हाल में जीयो मनरेगा को प्रारम्भ किया गया है । मनरेगा अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का टैगिंग कराया जा रहा है तथा परिसम्पत्तियों के फोटोग्राफ को मनरेगा के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा ताकि कोई भी व्यक्ति वेबसाईट पर जाकर कार्यों की स्थिति देख सके । मनरेगा एवं समाज कल्याण विभाग के अभिसरण से वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराने का लक्ष्य है । मनरेगा योजना में पारदर्शिता हेतु सामाजिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था है । सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी के संचालन हेतु निदेशक सहित राज्य स्तरीय 7 पद एवं जिलास्तरीय 62, डिस्ट्रिक्ट रिर्सोस टीम की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । साथ ही मनरेगा योजना अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निष्पादन एवं सुनवाई हेतु स्वतंत्र प्राधिकार 24 लोकपाल की नियुक्ति की गई है, शेष 14 जिलों में लोकपाल चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । मनरेगा अन्तर्गत नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है । जिसके तहत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सेंट्रल नोडल एकाऊंट से सीधे उनके खाते में किया जाता है । योजनाओं में पारदर्शिता लाने एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन सुनिश्चित करने हेतु 48 स्टेट क्वालिटी मोनिटर तैनात किये गये हैं । महोदय, इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास के कार्यान्वयन हेतु प्रथम किस्त केन्द्रांश के रूप में 1724 करोड़ 82 लाख रू0 विमुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त पूर्व वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश के लंबित राज्यांश के रूप में 399 करोड़ 45 लाख रू0 विमुक्त किये गये हैं । विमुक्त राशि के विरूद्ध देय राज्यांश के रूप में 1362 करोड़ 75 लाख 13 हजार रू0 देय होता है । इसी राशि में से पूर्व वर्ष में अग्रिम राज्यांश दी गई राशि 87 करोड़ 11 लाख रू0 का समायोजन के बाद 1275 करोड़ 66 लाख 13 हजार रू0 अनुमान होता है । उक्त राशि के विरूद्ध मूल बजट उपबंध 515 करोड़ 61 लाख रू0 हैं तथा शेष 760 करोड़ 5 लाख 13 हजार रू0 द्वितीय अनुपूरक 2016 के माध्यम से उपबंध का प्रस्ताव है । राज्य सरकार द्वारा राज्य के 300 प्रखंडों में गरीबी निवारण हेतु बिहार ट्रांसपरेटीव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका-2 के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है एवं जिलों में 10 अगस्त 2016 से प्रारम्भ किया गया है । इसमें मुख्य समुदायिक संस्थाओं का विकास, समुदायिक निवेश निधि, स्वास्थ्य सम्पोषण एवं स्वच्छता तक पहुँच नवाचार एवं साझीदारी है । यह परियोजना विश्व बैंक सम्पोषित है । जिसके अन्तर्गत वित्तीय भार का 70 प्रतिशत विश्व बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा सम्पोषित किया जाना है एवं शेष 30 प्रतिशत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । योजना एवं विकास विभाग के द्वारा बिहार ट्रांसपरेटीव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका-2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष

2016-17 में बाह्य सम्पोषित मद में 350 करोड़ रू0 एवं राज्यांश मद में 75 करोड़ अर्थात् 425 करोड़ रू0 उद्व्यय की राशि उपलबध करायी गयी है । फलस्वरूप इस अतिरिक्त राशि का उपबंध द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से किया जायेगा । महोदय, हमारी जो योजना है, उसमें जो मनरेगा योजना है, उसमें अभी तक भारत सरकार के पास 2014-15 एवं 2015-16 एवं पूर्व में वित्तीय वर्ष में 516 करोड़ सामग्री मद की केन्द्रांश की राशि राज्य सरकार ने वहन किया है । जिसे अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है । इसी प्रकार से हम राज्य में जल संचय की योजना भी मनरेगा योजना के माध्यम से चला रहे हैं और जल संचय की योजना से महोदय, इसमें छोटे-छोटे चेक डैम का निर्माण हम करा रहे हैं । इस योजना का जहां-जहां निर्माण कराया गया है, वहां पर यह काफी प्रभावी हुआ है और भारत सरकार ने भी इसको काफी अच्छा लाईक किया है । भारत सरकार इस मोडल को पूरे देश में लागू करने की दिशा में पहल कर रही है । यह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है । इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्यांश हेतु 7 अरब 60 करोड़ 5 लाख 13 हजार रू0 एवं बिहार ट्रांसपरेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका-2 के क्रियान्वयन हेतु 425 करोड़ रू0, अर्थात् कुल 11 अरब 85 करोड़ 5 लाख 13 हजार रू0 का उपबंध द्वितीय अनुपूरक 2016 के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब समय हो गया ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, मैं आग्रह किनसे करूँ .....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन से आग्रह कीजिए ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय ।

टर्न-24/अंजनी/दि0 01.12.2016

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं अनुदान की मांग संबंधी मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2) अधिनियम-2016 एवं बिहार विनियोग(संख्या-3) अधिनियम-2016 के उपबंध के अतिरिक्त 11,85,05,13,000/- (ग्यारह अरब पचासी करोड़ पांच लाख तेरह हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम-2016 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम-2016 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01- कृषि विभाग के संबंध में 53,40,49,000/-(तिरपन करोड़ चालीस लाख उनचास हजार) रूपये

मांग संख्या-02- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 37,57,65,000/-(सैंतीस करोड़ संतावन लाख पैंसठ हजार) रूपये

मांग संख्या-03- भवन निर्माण विभाग के संबंध में 59,38,42,000/-(उनसठ करोड़ अड़तीस लाख बयालीस हजार) रूपये

मांग संख्या-04- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,62,50,74,000/-(एक अरब बासठ करोड़ पचास लाख चौहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या-07- निगरानी विभाग के संबंध में 39,83,000/-(उनचालीस लाख तिरासी हजार) रूपये

मांग संख्या-08- कला, सस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,000/-(एक हजार) रूपये

मांग संख्या-09- सहकारिता विभाग के संबंध में 24,26,000/-(चौबीस लाख छब्बीस हजार) रूपये

मांग संख्या–12– वित्त विभाग के संबंध में 25,00,000/–(पच्चीस लाख) रूपये

मांग संख्या–15– पेंशन के संबंध में 10,00,000/–(दस लाख) रूपये

मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 8,39,000/–(आठ लाख उनचालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–20– स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 2,39,76,89,000/–(दो अरब उनचालीस करोड़ छिहत्तर लाख नवासी हजार) रूपये

मांग संख्या–21– शिक्षा विभाग के संबंध में 15,95,000/–(पन्द्रह लाख पनचानवे हजार) रूपये

मांग संख्या–22– गृह विभाग के संबंध में 1,88,18,45,000/–(एक अरब अठासी करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–23– उद्योग विभाग के संबंध में 7,06,62,000/–(सात करोड़ छः लाख बासठ हजार) रूपये

मांग संख्या–25– सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 5,00,00,000/–(पांच करोड़) रूपये

मांग संख्या–26– श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 48,01,000/–(अड़तालीस लाख एक हजार) रूपये

मांग संख्या–27– विधि विभाग के संबंध में 3,96,05,000/–(तीन करोड़ छियानवे लाख पांच हजार) रूपये

मांग संख्या–30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में 11,01,40,000/–(ग्यारह करोड़ एक लाख चालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–31– संसदीय कार्य विभाग के संबंध में 4,00,000/–(चार लाख) रूपये

मांग संख्या–32– विधान मंडल के संबंध में 1,48,80,000/–(एक करोड़ अड़तालीस लाख अस्सी हजार) रूपये

मांग संख्या–33– सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 1,32,33,38,000/–(एक अरब बत्तीस करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस हजार) रूपये

मांग संख्या–35– योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 27,23,60,000/–(सत्ताइस करोड़ तेइस लाख साठ हजार) रूपये

मांग संख्या–36– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 14,00,00,000/–(चौदह करोड़) रूपये ।

मांग संख्या–38– निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संबंध में 23,75,000/–(तेइस लाख पचहत्तर हजार) रूपये

मांग संख्या–39– आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 11,41,21,30,000/–(ग्यारह अरब एकतालीस करोड़ इक्कीस लाख तीस हजार) रूपये

मांग संख्या–40– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 6,98,99,000/–(छः करोड़ अनठानवे लाख निन्यानवे हजार) रूपये

मांग संख्या–41– पथ निर्माण विभाग के संबंध में 3,58,00,01,000/–(तीन अरब अनठावन करोड़ एक हजार) रूपये

मांग संख्या–43– विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 15,53,65,000/–(पन्द्रह करोड़ तिरपन लाख पैंसठ हजार) रूपये

मांग संख्या–44– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 13,08,56,000/–(तेरह करोड़ आठ लाख छप्पन हजार) रूपये

मांग संख्या–45– गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 83,37,31,000/–(तिरासी करोड़ सैंतीस लाख एकतीस हजार) रूपये

मांग संख्या–46– पर्यटन विभाग के संबंध में 61,87,18,000/–(एकसठ करोड़ सतासी लाख अठारह हजार) रूपये

मांग संख्या–47– परिवहन विभाग के संबंध में 4,48,50,000/–(चार करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार) रूपये

मांग संख्या–48– नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 2,74,51,85,000/–(दो अरब चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पचासी हजार) रूपये

मांग संख्या–49– जल संसाधन विभाग के संबंध में 3,01,34,41,000/–(तीन अरब एक करोड़ चौंतीस लाख एकतालीस हजार) रूपये

मांग संख्या–50– लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2016.

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

"बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक,2016" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक,2016" को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक,2016" पर विचार हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक,2016" पर विचार हो ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि-

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-25/शंभु/01.12.16

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो।''

महोदय, जैसा कि अभी वित्तीय वर्ष 2016-17 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के द्वारा स्वीकृत किया गया है या पास किया गया है। संवैधानिक जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुरूप राशि तो इस सदन ने स्वीकृत कर दिया, मगर खर्च करने का औथराइजेशन के लिए ये विनियोग विधेयक आता है और वह विनियोग विधेयक प्रस्तुत है और स्वीकृति के पश्चात् मैं बोल रहा हूँ। महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने अपने संसदीय जीवन में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष आज तक नहीं देखा । यदि कोई जनहित से संबंधित मामला होता, अत्याचार से संबंधित मामला होता, स्टेट को नुकसान होने से संबंधित मामला होता तो उसमें थोड़ा बहुत चकचुक चलता है, टकराव चलता है, मगर पहले दिन बड़े आराम से और दूसरे दिन में जो बातें हुई उन बातों का निदान आपके कार्यालय कक्ष में आपके द्वारा सभी दल के नेताओं को बुलाया गया और उसका निदान एक तरह से निकल गया, मगर अब कोई आदमी वित्तीय कार्य को भी- मतलब खासतौर पर विपक्ष अगर वित्तीय कार्य को भी इतनी अगंभीरता से ले तो मैं कह सकता हूँ कि यह तो दिवालियापन है विपक्ष का। महोदय, मुझको लगता है कि विपक्ष ने एक सोची समझी राजनीति या रणनीति के तहत जो दिल्ली में दिल्ली की सरकार का और प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी का जो विभिन्न फ्रंट पर फोल्योर है और उस फेल्योर की चर्चा आज देश में बिहार राज्य में आम होने लगी है तो उससे बचने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वह तरीका मुझको लगता है कि बेहतर तरीका नहीं है, अच्छा है उसके लिए अलग अलग कई फ्रंट खुले हुए हैं उस फ्रंट का इस्तेमाल करके वे अपनी बात रख सकते थे तो मुझे शंका होती है संभवतः नरेन्द्र मोदी जी ने जो एक वादा किया था, अब उसको कहते हैं कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया तो चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी जी ने जो यह वादा किया देश की जनता के सामने कि हम गरीबों को 15 से 20 लाख रूपया हमारी सरकार बनी तो हम मुहैय्या करायेंगे। मुझको लगता है कि इसकी जो चर्चा आजकल आम हो गयी है तो उसको विपक्ष छिपाना चाहता है। दूसरा महोदय, अभी जो नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ, तैयारी हुई और तैयारी के दौरान देश

के विभिन्न जिलों में मतलब नोटबंदी करने के पहले सुनियोजित ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने देश के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नाम पर जो जमीनें खरीदी और इसपर मीडिया से लेकर देश में सवाल जो उठने लगा कि भाई एकाएक कहां से इतना पैसा आ गया कि 600 कुछ जिलों में इन्होंने पार्टी के लिए जमीनें खरीद ली तो अब देश की जनता यह सवाल जरूर पूछती है कि जब आपकी सरकार नहीं थी तो उस जिला में आपका कार्यालय नहीं था और सरकार जब बन गयी तो पता नहीं नोटबंदी के पूर्व आपने सुनियोजित ढंग से देश के विभिन्न जिलों में कार्यालय की जमीन खरीदी है, वह भी सर्किल रेट से नीचे की कीमत पर या नकदी भुगतान पर तो आज देश की जनता इसका ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी, भारतीय जनता पार्टी से चाहती है और अगर यहां मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं ये, अगर ये इनमें नैतिकता है तो यह कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज से या लोक सभा की कमिटी से इसकी जॉच कराकर के इसका रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो मुझको लगता है कि इससे भी वे बचना चाहते हैं। अब मुझको लग रहा है कि अब आम हो गया है, गली-गली में, गांव-गांव में यह नारा लगने लगा है कि 15 लाख का देकर झांसा, पूरे देश को कैसा फांसा, यह भी नारा आज आम आदमी बोल रहा है। दूसरा अच्छे दिन की क्या पहचान, लाइन लगा है हिन्दुस्तान। मुझको लगता है कि कोई ऐसी घटना मैंने कल भी कहा था कि इसी हाऊस में उनके कई ऐसे नेताओं ने वैसा आचरण किया जो नहीं करना चाहिए था, तब भी हाऊस चला और हाऊस में ये नौबत नहीं आयी। मगर बात आपके कक्ष में करते हैं कुछ और फिर आते हैं यहां तो करते हैं कुछ और फिर इस तरफ आकर मंत्रियों को भी जब समय रहता है तो कहते हैं कि मंत्री जी जरा ये वाला लिख दीजिए- कौन सा चरित्र है, किस तरह की परंपरा आप कायम करना चाहते हैं, कौन सी नैतिक जिम्मेवारी आप लेकर चल रहे हैं ? महोदय, अब चूंकि हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अपने विभाग के बारे में विस्तार से चर्चा की है उसी चर्चा के क्रम में यह भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडिंग पैटर्न बदला है उस फंडिंग पैटर्न के बदलने के कारण बिहार जैसे गरीब राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, मगर फिर भी हम वो नुकसान उठा रहे हैं, मगर जो जनकल्याणकारी योजना है या यूँ कहिये कि बिहार सरकार ने सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी, हमारी सरकार, हमारी पार्टी गठबंधन के लोगों ने जो निश्चय किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो गठबंधन था हमारा। अब क्या है महोदय कि शराबबन्दी हुई। आपको स्मरण होगा कि सभी लोगों ने यहां पर आपके द्वारा संकल्प दिलाया गया था और सबों ने संकल्प लिया तो वहीं हम कहते हैं कि अरे भैय्या अगर झूठ बोलना है तो हम वहीं दोहराऐंगे कि वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। क्रमशः।

टर्न–26/ अशोक/ 01.12.2016

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : क्रमश : अब यहां संकल्प लिये, ठीक बोल रहे थे विजेन्द्र यादव जी कि संसदीय परम्परा और संसदीय जिम्मेदारी के लिए इससे बड़ा मंदिर कोई दूसरा नहीं हो सकता है और इसमें पक्ष और विपक्ष गरीब और अमीर जो भी चुन कर आता है वह अपनी बात यहां रखता है । मगर अपनी बात बोलना तो सुनिये तो ठीक और सरकार की बात को वे सुनना नहीं चाहते हैं । महोदय, अब हमारे गठबंधन की तरफ से जनता से चुनाव के दौरान ही एकरारनामा बनाया गया था कि हमारी सरकार बनी तो हम सात निश्चय के लिए यह–यह कार्यक्रम हम लागू करेंगे । उसमें आर्थिक हल युवा का बल, नली, गली, सड़क और युवा को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, महिला को आरक्षण – ये सारी बातें हैं तो महोदय, अब जब इन कार्यक्रमों को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों में जाकर के आम लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में जागृत कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं ? यह तो धोखा है, ये बोलते हैं कि यह धोखा है । शराबबन्दी हो गई, यहां संकल्प ले लिया फिर तरह –तरह का उसमें नुख्स वो निकाल रहे है कि साहब यह होता तो ठीक होता, वह होता तो ठीक होता, तो मुझको लगता है कि इतना कंफ्यूज्ड विपक्ष आज तक नहीं देखा कि जो एक बार तय कर लेता है तो उसपर स्थिर नहीं होता है । महोदय, चूंकि सारी बातें आ गई हैं मतलब सारी बातें बोल रहे हैं कि आ गई है, महोदय यह जो विनियोग विधेयक है तो जो स्वीकृति प्रदान की गई है द्वितीय अनुपूरक का इसमें तीन मद हैं, एक तो राज्य योजना मद है, दूसरा गैर–योजना मद है और तीसरा केन्द्रीय योजना का मद है । अब राज्य योजना मद से जो राशि खर्चा होती है, उससे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं हलांकि गैर–योजना से कुछ कार्य होते हैं एसेट्स क्रियेशन का मगर राज्य योजना विशुद्ध रूप से राज्य का एसेट्स क्रियेशन की योजना है चाहे समाज हो, गांव हो, बिहार हो । अब इसमें महोदय, चूंकि बजट जो मूल बजट था तो सबको मालूम है कि 1 लाख 44 हजार 696.27 करोड़ का फरवरी में ही पास हुआ था । फिर प्रथम अनुपूरक लेकर आये इसमें 16 हजार 859.99 करोड़ रूपया इस सदन ने स्वीकृति दिया खर्च करने का और फिर अभी जो द्वितीय अनुपूरक के तहत यह जो विनियोग संख्या–4 है महोदय, इसमें 4 हजार 461.70 करोड़ है, मतलब कि अब हमारा ये दोनों मिला देते हैं तो 1 लाख 66 हजार 17.96 करोड़ रूपये से राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनायें, सात निश्चय के विभिन्न कार्यक्रम, मैं थोड़ा फोकस इस वजह से भी डालना चाहता हूँ महोदय सात निश्चय पर कि सात

निश्चय का जो कार्यक्रम है, यह सामाजिक परिवर्त्तन का कार्यक्रम है, यह सात निश्चय का जो कार्यक्रम है यह सांस्कृतिक परिवर्त्तन का कार्यक्रम है और जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह गठबन्धन की सरकार समाजिक परिवर्त्तन की दिशा में और सांस्कृतिक परिवर्त्तन की दिशा में जनता को जागृत कर रही है और काम जो कर रही है उसके लिए राशि मुहैया कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा और कार्यान्वयन की समीक्षा कर रही है तो यही गैर-जिम्मेदार विपक्ष क्या क्या बोलता उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है । महोदय, मैं बहुत संक्षेप में राज्य योजना मद में अभी जो स्वीकृत की गयी है राशि 2 हजार 838.67 करोड़, इसमें क्या-क्या है महोदय, जो हमारी राशि घट रही है और उसके लिए प्रावधान कर रहे हैं वह है प्रधान मंत्री आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना में राज्यांश मद में 425 करोड़ रूपये, दूसरा गरीबी निवारण हेतु परिवर्त्तनकारी विकास परियोजना जीविका-टू कार्यक्रम सम्पोषित में 300 करोड़ रूपये और सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना नबार्ड सम्पोषित में 175.38 करोड़ रूपये, बिहटा हवाई अड्डा, बड़ी यहां के लोगों की मांग थी, सबको अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन रहा है तो राज्य सरकार ने यह तय किया और उसके लिए राशि 147.25 करोड़ रूपये बिहटा हवाई अड्डे के लिए की जा रही है महोदय । गैर योजना मद में महोदय, 1591.14 करोड़ रूपये हैं और केन्द्रीय योजना, गत योजना में 31.88 करोड़ रूपये हैं महोदय । अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ आंकड़ा है यह, इसको मैं रख दूं, इसको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, वह कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

(परिशिष्ट-1 द्रष्टव्य)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री : अंत में एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। महोदय, इन्होंने कहा हमारे ग्रामीण विकास मंत्री ने कि जो फंडिंग पैटर्न बदला उसके वजह से भी हुआ, मगर अभी की जो स्थिति है महोदय, जो नोटबंदी के निर्णय हुये है, हमलोगों ने उसका विरोध नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कालाधन भी निकलना चाहिए, बेनामी धन भी निकलना चाहिए, और हम जो करते हैं ठोक ठठाकर और पूरी समीक्षा और तैयारी करके करते हैं,मगर अभी महोदय, अब यह डिमोनेटाईजेशन के कारण आने वाले मार्च तक में, अप्रील या हो सकता है यह छः महीना भी जाय महोदय, इसके कारण अर्थ व्यवस्था में मंदी आयेगी और महोदय अर्थ व्यवस्था में मंदी आयेगी तो व्यवसाय कम होगा और जब व्यवसाय कम होगा तो आर्थिक गति भी घटेगी और जब आर्थिक गतिविधि घटेगी तो कर संग्रह भी कम होगा, इस खतरा को भी हम

झेल रहे हैं वह फंडिंग पैटर्न को तो झेल ही रहे हैं मगर अभी जो कार्रवाई हो रही है इसके कारण जो अर्थ व्यवस्था पर और टैक्स संग्रह पर जो असर पड़ना है, उससे कम होना है टैक्स कलेक्शन का, अभी महोदय, आप जानते हैं कि जी.एस.टी. लागू होना है, हमारे कामर्शियल टैक्स मिनिस्टर बैठे हैं कल इनको जाना है मीटिंग में लोगों ने अबतक 2016-17 के वित्तीय वर्ष में वाणिज्य-कर संग्रह को ही आधार बना कर इसमें स्टेट का हिस्सा मिलेगा महोदय, इससे कम कर संग्रह होने पर हमारा आधार घटेगा और कम कर-संग्रह इस वजह से होगा, इसके वजह से, डिमोनेटाईजेशन के कारण जो अर्थ व्यवस्था पर मार जो हो रही है इसके कारण मुझको लगता है, हमारे कामर्शियल टैक्स मिनिस्टर ये मिटिंग में केन्द्र सरकार के समक्ष यह सवाल उठायेंगे, महोदय, इस वजह से मैं सदन से विपक्ष की अनुपस्थिति में और मिडिया के द्वारा विपक्ष को सुनाकर कि इस राशि से राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा इसलिए इसको सर्वसम्मति से इसको स्वीकृत किया जाय ।

टर्न-27:ज्योति

01-12-2016

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 स्वीकृत हो । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2016 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 01-12-2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 55 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनॉक 2 दिसम्बर 2016 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*****

परिशिष्ट–1

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को उपस्थापित किया गया। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में **4461.70** करोड़ रूपये (चार हजार चार सौ एकसठ करोड़ सत्तर लाख रूपये) प्रस्तावित की गयी है।

राज्य योजना मद में **2838.67** करोड़ रूपये (दो हजार आठ सौ अड़तीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये) प्रस्तावित है। इसमें मुख्य प्रावधान 760.05 करोड़ रूपये(सात सौ साठ करोड़ पाँच लाख रूपये) प्रधानमंत्री आवास योजना (इंदिरा आवास योजना) में राज्यांश मद में, 425.00 करोड़ रूपये (चार सौ पचीस करोड़ रूपये) गरीबी निवारण हेतु बिहार परिवर्त्तनकारी विकास परियोजना, जीविका–II कार्यक्रम (बाह्य सम्पोषित) में, 300.00 करोड़ रूपये (तीन सौ करोड़ रूपये) सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना (नाबार्ड सम्पोषित) में, 175.38 करोड़ रूपये (एक सौ पचहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रूपये) परिवार कल्याण से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण अस्पतालों के कर्मियों के स्थापना मद में, 160.00 करोड़ रूपये (एक सौ साठ करोड़ रूपये) बिहटा हवाई अड्डा के निर्माण में, 147.25 करोड़ रूपये (एक सौ सैंतालीस करोड़ पचीस लाख रूपये) सबके लिए आवास मिशन (केन्द्रांश में 57.25 करोड़ रूपये (सन्तावन करोड़ पचीस लाख रूपये) एवं राज्यांश में 90.00 करोड़ रूपये (नब्बे करोड़ रूपये) के क्रियान्वयन में, 146.00 करोड़ रूपये (एक सौ छियालिस करोड़ रूपये) केन्द्रीय सड़क निधि में, 104.32 करोड़ रूपये (एक सौ चार करोड़ बतीस लाख रूपये) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन हेतु स्थापना मद में, 100.00 करोड़ रूपये(एक सौ करोड़ रूपये) 40 पुलिस जिलों एवं 4 रेल जेलों के 1056 थानों में सी०सी०टी०वी० कैमरा में व्यय हेतु प्रस्तावित है।

गैर योजना मद में **1591.14** करोड़ रूपये (एक हजार पाँच सौ एकानवे करोड़ चौदह लाख रूपये) प्रभृत राशि सहित प्रस्तावित है। इसमें मुख्य प्रावधान 991.00 करोड़ रूपये (नौ सौ एकानवे करोड़ रूपये) प्राकृतिक विपत्ति के कारण पीड़ित जनता को नकद अनुदान, खाद्यान्न इत्यादि में, 200.00 करोड़ रूपए (दो सौ करोड़ रूपये) क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों को कृषि इनपुट अनुदान में, 85.85 करोड़ रूपए (पचासी करोड़ पचासी लाख रूपये) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी निकायों को सहायक अनुदान में एवं 69.27 करोड़ रूपए (उनहत्तर करोड़ सताईस लाख रूपये) चीनी निगम के कर्मियों के वेतनादि भुगतान में व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

केन्द्रीय योजनागत योजना मद में 31.88 करोड़ रूपए (अड़तीस करोड़ अट्ठासी लाख रूपये) प्रस्तावित है । इसमें मुख्य प्रावधान 16.46 करोड़ रूपए (सोलह करोड़ छियालीस लाख रूपये) भारत साख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना में, 8.00 करोड़ रूपए

(आठ करोड़ रूपये) नीली क्रान्ति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन में, 4.76 करोड़ रूपए (चार करोड़ छियहत्तर लाख रूपये) लघु सिंचाई गणना परियोजना में एवं 2.00 करोड़ रूपए (दो करोड़ रूपये) वन बन्धु कल्याण योजना में व्यय हेतु प्रस्तावित है ।

बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2016 द्वारा कुल **4461.70** करोड़ रूपये (चार हजार चार सौ एकसठ करोड़ सत्तर लाख रूपये) की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है। विनियोजन राशि में **4390.41** करोड़ रूपये (चार हजार तीन सौ नब्बे करोड़ एकतालीस लाख रूपये) मतदेय एवं **71.29** करोड़ रूपये (एकहत्तर करोड़ उन्तीस लाख रूपये) भारित है।

द्वितीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2016 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदन से अनुरोध है कि द्वितीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2016 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए ध्वनिमत से पारित किया जाए ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे।

********** –:जय हिन्द:– **********